बजट विशेषः 2016–17

आम लोगों के लिए ‘खास’ बजट

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

बजट विशेषः 2016–17

आम लोगों के लिए 'खास' बजट

संकलनकर्ता

शिवानन्द द्विवेदी

सहयोग

शलैन्द्र शुक्ला

Cover Design & Layout

Vikas Saini

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

रिसर्च फाउंडेशन

अनुक्रमणिका

क्र.सं	लेख	पेज न.
01	प्राक्कथन	4
02	छवि बदलने वाला बजट **– मेघनाद देसाई**	6
03	बजट 2016–17 में की गई महत्वीपूर्ण घोषणाएं	9
04	गांवों की समृद्धि का संकल्प **– नरेंद्र सिंह तोमर**	14
05	Key Features of Budget 2016-2017	16
06	nhanced focus on Higher and Skills Education Welcome! **– Rohan Joshi**	32
07	Improving quality of travel	34
08	Budget Exposes Gandhis, Irrelevance of the Left **– Balbir Punj**	38
09	The 2016-17 Budget : A Positive step in India's Transformation Process **– Mukul Asher**	39

प्राक्कथन

गत २९ फरवरी-२०१६ को पूरे देश की निगाहें सर्वोच्च पंचायत लोकसभा की तरफ थीं। भाजपा-नीत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली आम-बजट पेश कर रहे थे। बजट भाषण समाप्त होने के बाद एक प्रतिक्रिया तो लगभग सभी विश्लेषकों ने दी कि यह 'गाँव-गिरान' को समर्पित बजट है, यह गरीब-मजदूर और किसान को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। वैसे तो देश ने संसद की पटल से अनेकों बजट देखा है, लेकिन इस बार के बजट को देखकर सुदूर गाँव में बैठा कोई किसान, कोई आम जन भी कह सकता था कि श्ये मेरा बजट हैश। इसमें कोई शक नही कि आम जन के लिहाज से यह बजट बेहद खास रहा है। इस बजट में किसानों की आय को दोगुना करने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत २८.५ लाख हेक्टेलयर भूमिपर सिंचाई सुविधा शुरू किये जाने, ८९ सिंचाई परियोजनाओं को फास्टो ट्रैक करने जैसे तमाम कृषि योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है। मार्च २०१७ तक १४ करोड़ कृषि जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जाने का लक्ष्य, अपने आप में एक क्रांतिकारी अभियान है जिससे कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव को अमली जामा पहनाया जा सकता है। कृषि ऋण का लक्ष्य ९ लाख तक का रखा गया है। गरीबों की बेहतरी के लिए समर्पित इस बजट में ऐसे तमाम प्रावधान प्रमुखता से रखे गये हैं जिनसे गरीब से गरीब परिवार भी लाभान्वित हो सके। गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शिन मुहैया कराने के लिए ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि २०१६-१७ में १.५ करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। परिवार की महिला सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। भारत को एक स्वस्थ देश बनाने की दिशा में पहल करते हुए वित्त मंत्री ने इस बजट में कुछ ऐसी योजनाओं को स्थान दिया है, जो अभी तक जनता की पहुँच से दूर थीं। नई स्वा स्वास्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति परिवार १ लाख रुपए और वरिष्ठत नागरिकों को अतिरिक्तस ३० हजार रुपए तक के स्वास्थ्य कवर प्रदान किए जाने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराने के लिहाज से वर्ष २०१६-१७ में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत ३,००० स्टोर खोले जाने का लक्ष्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों को मुख्यधारा के उद्यम में लाकर बतौर उद्यमी उन्हें स्थापित करने की दिशा में इस बजट में खास प्रावधान हैं। उद्यमियों के लिए एक नई आर्थिक प्रणाली का गठन किये जाने की बात की गयी है। साथ ही एमएसएमई मंत्रालय में एससी/एसटी हब का निर्माण करने की बात भी इस बजट का हिस्सा है। पशुधन कल्याण को देखते हुए पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 'पशुधन संजीवनी' करने की बात बजट में कही गयी है। पंचायतों के सशक्तिकरण एवं विकास पर बल देते हुए वित्त मंत्री ने प्रति ग्राम पंचायत ८१ लाख रुपए एवं प्रति नगर पालिका २१ करोड़ रुपए अनुदान सहायता देने का प्रावधान रखा है। २०१८ मई तक गाँव-गाँव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य इस बजट में चिन्हित किया गया

है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत १५०० बहु-कौशल प्रशिक्षण सेंटर खोलने की बात भी इस बजट में की गयी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए ५५,००० करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा भी आम जन से जुड़े तमाम प्रावधानों पर विशेष विचार इस बजट में किया गया है। वहीं दुसरी तरफ रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु में रेलवे के विकास एवं अत्याधुनिक सुविधाओं के लिहाज से शानदार बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का रेल बजट हवा-हवाई बातों का रेल बजट न होकर जन-सुविधाओं को सुलभ बनाने वाला बजट है। रेलवे के विकास, यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रेल बजट में रखा गया है। यह सबकुछ बिना किराया बढाए किया गया है। हालांकि भाजपा-नीत केंद्र सरकार के अभी बाईस महीने ही हुए हैं लेकिन रेलवे के क्षेत्र में व्यापक सुधार जमीन पर दिखने लगे हैं। चाहें आधुनिकीकरण का मसला हो या स्वच्छता का ख्याल अथवा यात्रियों की सुविधा का मसला ही क्यों न हो, भारतीय रेल अब बेहतर सेवा मुहैया कराती दिख रही है।

अगर एक पंक्ति में पूरे बजट का सारांश कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि बजट-२०१६-१७ आम लोगों को मिला एक 'खास बजट' है। अर्थात, An special budget for common man. इस बजट ने यह साबित किया है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार आम जन के हितों को लेकर सर्वाधिक चिंतित है। उसकी चिंता के केंद्र में आम जन की सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर वो सतत काम कर रही है। इस ई-बुकलेट के माध्यम से हम बजट के प्रमुख बिन्दुओं, उसके विस्तृत विश्लेषण, एवं समाचार-पत्र में छपे कवरेज को जनता के बीच ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ई-बुकलेट में कुछ समाचार-पत्रों के स्कैन कॉपी, उनमे छपे लेख आदि को साभार लिया गया है। जिन अखबारों, वेबसाइट्स से लेख एवं स्कैन कॉपी आदि लिया गया है, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउन्डेशन सभी का आभार व्यक्त करता है।

शिवानन्द द्विवेदी
रिसर्च फेलो
डॉ श्यामा प्रसाद मुकर्जी रिसर्च फाउंडेशन

छवि बदलने वाला बजट

● मेघनाद देसाई

कृषि और ग्रामीण भारत की चिंताओं पर केंद्रित बजट में नए आर्थिक चिंतन की झलक को साफ देखा जा सकता है।

वर्तमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट बहुत ही संतुलित और सधा हुआ है। बजट में ग्रामीण भारत की चिंताओं और समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। ऐसा पहली बार है जब किसी वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र और किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और एक तय सीमा अवधि में किसानों की आय को न सिर्फ बढ़ाने, बल्कि उसे दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि सेवा और अन्य क्षेत्रों में देश की तमाम आर्थिक तरक्की के बावजूद किसान लगातार बदहाल हो रहे थे और खुद को उपेक्षित भी महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए भी था, क्योंकि विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के शुरुआती दो बजटों को किसान विरोधी और गरीब विरोधी करार दिया था और इस तरह देश में सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने का काम किया जा रहा था।

बिहार के चुनावों में मिली हार की एक वजह यह भी रही कि सरकार के तमाम अच्छे कामों के बावजूद आम लोगों को कोई खास फायदा नहीं मिला और यह कहा गया कि मोदी सरकार की चिंता के केंद्र में सिर्फ शहरी भारत है। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को सूट-बूट की सरकार की संज्ञा प्रदान की। ऐसी स्थिति में यह जरूरी था कि मोदी सरकार यह साफ करती कि उसका ध्यान शहरी भारत अथवा ग्रामीण भारत पर नहीं, बल्कि समग्र भारत के विकास पर है। वर्तमान बजट से सरकार ने अपने खिलाफ बन रही धारणा को तोड़ने की कोशिश की है और इस रूप में वह देशवासियों को एक नया संदेश देने में कामयाब रही है। वैसे किसी सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि मोदी सरकार के शुरुआती दो बजटों को इस बजट के साथ जोड़कर देखा जाए। उसके शुरुआती दो बजट जहां शहरी भारत के विकास पर अधिक केंद्रित थे तो वर्तमान बजट ग्रामीण भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और यह सही भी है, क्योंकि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के लिए यह जरूरी है कि हम शहरी भारत और ग्रामीण भारत के बीच की दूरियों को निरंतर कम करें।

इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। गांवों में रोजगार का एक बड़ा जरिया बनकर उभरे मनरेगा कार्यक्रम के लिए भी सरकार ने अच्छा-खासा धन उपलब्ध कराया है और इस योजना को

ग्रामीण ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसके अलावा सिंचाई योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। लगातार गिर रहे भूमिगत जल के स्तर को देखते हुए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ असिंचित खेतों को पानी मिल सकेगा, बल्कि जल का बेहतर प्रबंधन भी किया जा सकेगा, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। १वित्तमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में तमाम छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है, जो दीर्घकालिक दृष्टि से बेहद अहम हैं। ऐसी ही एक योजना सभी घरों में एलपीजी उपलब्ध कराने की है। इससे पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, साथ ही महिलाओं को ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करने से होने वाले तमाम रोगों से भी निजात मिलेगी। इसी तरह देश के १८,५०० गांवों में एक मई, २०१८ तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां तक सवाल इस बजट के लोकप्रिय अथवा सुधारवादी होने का है तो मैं इसे एक राजनीतिक बजट के तौर पर देखता हूं। यह बजट सामान्य बजट से भिन्न प्रकार का है, जिसमें आम लोगों की जरूरतों से जुड़ी छोटी-छोटी बातों तक का ध्यान रखा गया है।

हालांकि यह भी सही है कि बजट में बड़ी-बड़ी बातें अथवा सुधार का कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। श्रम बाजार में सुधार को लेकर कुछ अपेक्षाएं थीं कि सरकार कोई कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जीएसटी के मामले में भी कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई गई सिवाय इसके कि सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक बैंकों में सुधार के लिए कदम उठाने और २५००० करोड़ रुपये मुहैया कराने की बात है तो यह पर्याप्त नहीं। वास्तव में देखा जाए तो सरकार ने बैंकों की हालत में सुधार लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय रीस्ट्रक्चरिंग करने का ही काम किया है। इसी तरह रोजगार सृजन की गति तेज करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पर बल दिया गया है, जो एक सही कदम है। इस समय सरकार के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता का मामला युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन है। रोजगार के सृजन की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है और इस कारण बजट पर युवाओं का बहुत ध्यान भी है। इस दिशा में मोदी सरकार ने निजी उद्यमिता को बढ़ावा देने की नीति का अनुसरण किया है और इसके लिए नव उद्यमियों को तमाम वित्तीय सुविधाओं के साथ कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है। उम्मीद है कि इस पहल से रोजगार सृजन में तेजी आएगी और युवाओं की अपेक्षाएं पूरी होंगी। यदि उद्योग जगत की बात करें तो उम्मीद थी कि सरकार कारपोरेट टैक्स में कमी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

काले धन के संदर्भ में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन यह घरेलू काले धन के मामले में ही कारगर होगा, न कि विदेशों में जमा काले धन के लिए। स्वास्थ्य बीमा कार्ड, इंश्योरेंस आदि के क्षेत्र में दी गई सहूलियतों से मध्यम वर्ग समेत आम लोगों को लाभ होगा। जहां तक टैक्स दरों की बात है तो इस दिशा में सरकार ने कोई खास घोषणा नहीं की है, सिवाय इसके कि पांच लाख तक आय सीमा वाले लोगों को कुछ छूट हासिल होगी। इस बारे में मेरा मानना है कि सरकार को आयकर के बजाय उपभोक्ता करों के बारे में विचार करना चाहिए। यह

इसलिए जरूरी है, क्योंकि तमाम प्रयासों और उपायों के बावजूद भी कराधार बढ़ाने में कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है और हमारी कुल आबादी में से तीन फीसद से भी कम लोग आयकर देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक अच्छा और अलग प्रकार का बजट है। बजट तैयार करते समय सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को भी ध्यान में रखा है, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव मुख्य हैं। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा जूनियर पार्टनर की भूमिका में है, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद है। ❍

जय किसान पृष्ठ >> 4

मेरा गांव मेरा देश पृष्ठ >> 5

समर्थ समाज पृष्ठ >> 6

बुनियाद पृष्ठ >> 7

कर कराधान पृष्ठ >> 8

अर्थसार पृष्ठ >> 9

मोदी-जेटली की जोड़ी ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही पहलुओं पर जबरदस्त संतुलन साधा

सशक्त गांव, समृद्ध भारत

लीक से हटकर बजट, गांव-गरीब-किसान-दलित और छोटे उद्यमियों का पूरा खयाल

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए बुनियादी ढांचे पर भी विशेष जोर

लोक-लुभावन घोषणाओं को अलविदा, पात्रों को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य

राजकिशोर/जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

समस्या में समाधान ढूढ़ने का हुनर मोदी सरकार को आता है। इस दफा लीक से हटकर बजट पेश कर इस सरकार ने यह दिखा भी दिया है। राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही पहलुओं पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जबर्दस्त संतुलन साधा है। गांव-गरीब-किसान-दलित और छोटे उद्यमियों का पूरा ख्याल तो रखा है, लेकिन आर्थिक सुधारों की दिशा में भी ठोस कदम बढ़ाए हैं। राजनीतिक व आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर प्रतिकूल परिस्थितियों से यह बजट दो-दो हाथ करता है। जेटली की मोदी दृष्टि शहरों की गलियों और अर्थशास्त्र के वैश्विक जंतर-मंतर में नहीं फंसी है। नौ स्तंभों पर टिकी नवभारत की रचना का मुख्य स्रोत गांवों और खेत-खलिहानों से होकर गुजरता है। सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोक-लुभावन घोषणाओं के दौर को जहां अलविदा कहा गया है, वहीं मदद के नाम पर खैरात देने के बजाय पात्रों को स्वावलंबी बनाने का स्पष्ट लक्ष्य और सुविचरित रणनीति बजट में है।

विपक्ष के आरोप ध्वस्त : आंकड़ों के मकड़जाल को तोड़ जेटली का बजट कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह सामाजिक और राजनीतिक स्वावलंबन की चेष्टा करता दिखता है। वैश्विक मंदी से मुकाबले के स्वदेशी नुस्खों की पिटारी से जेटली ने किसानों और नौजवानों को निकाला है। खेत और छोटे उद्योगों के साथ-साथ दलितों को समर्थ करने के पड़ावों से गुजरते इस बजट में भारत को खाद्य और आर्थिक स्तर पर स्वावलंबी बनाने की महत्वाकांक्षी और सटीक नीति के दर्शन होते हैं। रोजाना सबसे ज्यादा सड़क निर्माण लक्ष्य का रखा गया है, लेकिन उसमें भी गांवों के बीच संपर्क मार्गों को प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि यह गांव, गरीब और किसान का बजट है- तो यह सिर्फ जुमला नहीं लगता। सूट-बूट की सरकार या दलित विरोधी और आम आदमी के प्रति असंवेदनशील जैसे विपक्ष के आरोप इस बजट के बाद धुआं होना स्वाभाविक है।

- सबसे ज्यादा सड़क निर्माण लक्ष्य, गांवों के संपर्क मार्गों को भी प्राथमिकता
- कृषि क्षेत्र का बजट 25000 करोड़ से 44000 करोड़ किया
- खाद्य प्रसंस्करण में 100% एफडीआइ सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़

गांव-किसान पर कुर्बान

बजट पूरी तरह से गांव-किसान पर कुर्बान है। वित्त मंत्री ने अगर किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया तो उसे मजबूती देने के ठोस कदम भी उठाए हैं। कृषि क्षेत्र की रकम 25000 से 44000 करोड़ कर दी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटन 82000 से 88000 करोड़ कर दिया है। देश में छिपे काले धन को बाहर निकालने की सरकार जो योजना लाई है, उससे भी किसानों के हित जोड़े हैं। सामने आने वाले कालेधन का 7.5 फीसद कृषि क्षेत्र को मिलेगा। सेवाकर से भी 0.5 फीसद सेस कृषि को मिलेगा। पीएम ने हर किसान के एक बच्चे को नौकरी दिलाने का वादा किया था। फूड प्रोसेसिंग में सौ फीसद एफडीआइ उसी दिशा में बड़ा कदम है। सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ का ऐलान भी है।

सामाजिक विकास

दलितों को आगे लाने के लिए आरक्षण के सियासी दांव से मोदी आगे बढ़े हैं। ढाई लाख दलित उद्यमियों की फौज खड़ा करने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उनको इकाई लगाने तक में मदद करेगी। उनके उत्पाद खरीदेगी। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को 30 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। बुजुर्ग का इलाज होने पर 30 हजार अलग मिलेंगे। कई नवोदय भी खोले जाएंगे। लघु उद्योगों को राहत देने के लिए उनकी अनुमानित कर की रकम अक करोड़ के बजाय दो करोड़ रुपये तक मुक्त कर दी गई है।

उद्योग का शिकवा

कारपोरेट और उद्योग को लेकर कुछ भी उत्साहजनक न होने का आरोप है। साथ ही उन पर ज्यादा कर भी लगाए गए हैं, लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी के हालात में यह कुछ भी नहीं है। अतिरिक्त करों का सबसे ज्यादा बोझ आटो मोबाइल इंडस्ट्री पर डाला गया है। छोटी कारों से लेकर लग्जरी कारें तक महंगी हुई हैं। यह क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लेकिन राजकोषीय अनुशासन के चलते यहां पर कैंची चलानी पड़ी है। जैसा कि आर्थिक सर्वे में सरकार को आयकर से छूट की सीमा न बढ़ने की सलाह दी गई थी, उसी के अनुरूप वेतनभोगी कर्मचारियों को टैक्स में सीधे रियायत नहीं दी गई है। अलबत्ता होम लोन और किराये पर रह रहे लोगों को वित्त मंत्री ने जरूर राहत दी है।

बड़े आर्थिक सुधार

आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कई छोटे-छोटे कदम देश की विकास दर दहाई तक पहुंचाने का आधार बन सकते हैं। राजकोषीय संतुलन का ढांचा तैयार किया गया है। नेहरूयुगीन योजनागत और गैरयोजनागत खर्च आवंटन की निशानी को भी 2017 से अलविदा कहने की घोषणा कर दी गई है। अब बजट में सिर्फ राजस्व और पूंजीखाते से खर्च की श्रेणियां ही रहेंगी। पंचवर्षीय योजना मॉडल को भारत तिलांजलि देने जा रहा है। आयकर व अन्य कर के मकड़जाल के सरल करने के साथ पांच लाख करोड़ के आयकर संबंधी अदालतों में फंसे मामले सुलझाने का रोडमैप भी बजट देता है। जर्जर सरकारी बैंकों के सामने विलय करने के अलावा चारा नहीं है। इस फैसले को अमल में लाना आसान नहीं है, लेकिन सरकार इन बैंकों में हिस्सेदारी भी घटाने को तैयार दिखती है।

नए नजरिये का प्रदर्शन
सही दिशा में छोटा कदम
बुनियादी बदलाव का बजट

>> संपादकीय पृष्ठ

बजट 2016–17 में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

१. कृषि एवं किसानों के कल्याण पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित

क) किसानों की आय वर्ष २०२२ तक दोगुनी की जायेगी।

ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत २८.५ लाख हेक्टेरयर भूमिपर सिंचाई सुविधा शुरू की जायेगी।

ग) ८६ सिंचाई परियोजनाओं को फास्टे ट्रैक किया जायेगा, जिनके लिए अगले पांच वर्षों के दौरान ८६,५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इनमें से २३ परियोजनाओं को ३१ मार्च २०१७ से पहले पूरा किया जायेगा।

घ) नाबार्ड में २०,००० करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष बनाया जायेगा।

ङ) सिंचाई पर बाजार उधारी सहित कुल परिव्यय १२,१५७ करोड़ रुपये है।

च) ६,००० करोड रुपये की लागत पर बहुपक्षीय वित्त पोषण के साथ सतत भूजल प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है।

छ) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पांच लाख फार्म तालाबों एवं कुओं तथा जैविक उर्वरक के उत्पादन के लिए १० लाख कम्पोईस्टर गड्ढ़ों का निर्माण किया जायेगा।

ज) मार्च २०१७ तक १४ करोड़ कृषि जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जायेंगे।

झ) मृदा एवं बीज परीक्षण की सुविधाओं के साथ उर्वरक कंपनियों के २,००० आदर्श खुदरा केन्द्र अगले तीन वर्षों के दौरान खोले जाएंगे।

ञ) एकीकृत कृषि विपणन ई-प्लेकटफॉर्म को १४ अप्रैल, २०१६ को डॉ. अम्बेडकर के जन्मदिन पर राष्ट्र को समर्पित किया जायेगा।

२. वर्ष २०१६-१७ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर २७,००० करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे, जिसमें राज्य का हिस्सा भी शामिल है। पीएमजीएसवाई को पूरा करने की लक्षित अवधि को दो साल घटाकर वर्ष २०१९ कर दिया गया है, जबकि पहले इसे वर्ष २०२१ तक पूरा करना था।

३. वर्ष २०१६-१७ में नौ लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण के रूप में प्रदान किये जाएंगे।

४. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अनाजों की ऑनलाइन खरीदारी करेगा। इसके तहत समुचित पंजीकरण और खरीद की निगरानी करने से पारदर्शिता आयेगी और किसानों को सहूलियत होगी।

५. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 'पशुधन संजीवनी' शुरू किया जायेगा। 'नकुल स्वास्थ्य पत्र' जारी किये जाएंगे।

६. ग्रामीण क्षेत्र

क) १४वें वित्ता आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को २.८७ लाख करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति ग्राम पंचायत ८१ लाख रुपए एवं प्रति नगर पालिका २१ करोड़ रुपए अनुदान सहायता दी जाएगी।

ख) सूखाग्रस्त एवं ग्रामीण समस्याग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक प्रखंड को दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत सहायता दी जाएगी।

ग) ३०० रुरबन कलस्टहर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों को सहायता देंगे।

घ) सभी गांवों में १ मई २०१८ तक बिजली पहुंचा दी जाएगी।

ङ) अगले ३ वर्षों में लगभग ६ करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए ग्रामीण भारत के लिए एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन योजना प्रारंभ की जाएगी।

च) संशोधित राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्डों कार्यक्रम के जरिए भूमि रिकॉर्डों का आधुनिकीकरण।

छ) राष्ट्रीय ग्राम स्वाराज कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।

७. सरकारी सब्सिडियों एवं लाभों की लक्षित आपूर्ति जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गरीबों एवं हकदारों तक पहुंच सकें।

क) आधार संरचना का उपयोग करते हुए वित्तीभय एवं अन्यत सब्सिडियों आदि की लक्षित आपूर्ति के लिए नया कानून।

ख) उर्वरक में डीबीटी को प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया जाएगा।

ग) देश में कुल ५.३५ लाख उचित दर दुकानों में से ३ लाख दुकानों को मार्च २०१७ तक ऑटोमेट किया जाएगा।

८. मुद्रा- २०१६-१७ में १,८०,००० करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य।

९. सामाजिक क्षेत्र

क) गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए व्यापक अभियान प्रारंभ किया जाएगा। २०१६-१७ में १.५ करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। कुल ५ करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल करने के लिए यह योजना २ वर्ष और जारी रहेगी। परिवार की महिला सदस्यि के नाम पर एलपीजी कनेक्शंन दिए जाएंगे।

ख) नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रति परिवार १ लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ३० हजार रुपए तक के स्वास्थ्य कवर प्रदान किए जाएंगे।

ग) २०१६-१७ में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत ३,००० स्टोकर खोले जाएंगे।

घ) राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। डायलिसिस उपकरणों के कुछ विशेष हिस्सों को कर छूट दी जाएगी।

ङ) अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के लिए एक नई आर्थिक प्रणाली का गठन किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय में एससी/एसटी हब का निर्माण किया जाएगा।

१०. शिक्षा

क) जिन जिलों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं है, वहां पर ६२ नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

ख) विश्वि स्ततरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाएनों के रूप में उभरने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के १०-१० संस्थानों को एक सक्षमकारी नियामकीय ढांचा मुहैया कराया जाएगा।

ग) एक हजार करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी आधार के साथ उच्चढतर शिक्षा वित्ता पोषण एजेंसी की स्थाएपना की जाएगी।

घ) शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, मार्क्स-शीट, पुरस्कारों इत्यादि के लिए डिजिटल डिपोजिटरी की स्थापना की जायेगी।

११. कौशल

क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत १५०० बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थांन स्थाषपित किये जायेंगे।

ख) उद्योग जगत एवं शिक्षाविदों के साथ भागीदारी कर राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड स्थापित किया जायेगा।

ग) ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिये २२०० कॉलेजों, ३०० स्कूरलों, ५०० सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा ५० व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में उद्यमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

१२. रोजगार सृजन

क) भारत सरकार ईपीएफओ में नामांकन कराने वाले सभी नये कर्मचारियों के लिए रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के दौरान ८.३३ प्रतिशत का ईपीएस अंशदान अदा करेगी। यह उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका मासिक वेतन १५००० रुपये है।

ख) आयकर अधिनियम की धारा ८० जेजेएए को संशोधित किया जा रहा है, ताकि रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्साहनों का दायरा बढ़ सके।

ग) राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्लेमटफॉर्म के साथ राज्य रोजगार कार्यालयों को जोड़ा जायेगा।

घ) छोटी एवं मझोली दुकानों को स्वैच्छिक आधार पर सप्तांह में सातों दिन खुले रखने की इजाजत दी जायेगी। रिटेल क्षेत्र में नये रोजगार।

१३. बुनियादी ढांचा, निवेश, बैंकिंग, बीमा इत्यादि क्षेत्रों में उपाय

क) वर्ष २०१६-१७ में सड़कों और रेलवे के पूंजीगत व्यय पर २,१८,००० करोड़ रुपये

खर्च किये जाएंगे। इसमें शामिल हैं - पीएमजीएसवाई के लिए २७००० करोड़ रुपये

ख) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए ५५,००० करोड़ रुपये

ग) एनएचएआई बांडों के लिए १५,००० करोड़ रुपये

१४. रेलवे के लिए १,२१,००० करोड़ रुपये

क) बगैर उपयोग एवं कम इस्तेमाल वाली हवाई पट्टियों को एएआई बहाल करेगा और इसमें राज्य सरकारों के साथ भी भागीदारी होगी।

ख) परमिट प्रणाली को समाप्त कर सड़क परिवहन क्षेत्र (यात्री खंड) को खोला जाएगा। इससे गरीब एवं मध्यम वर्ग लाभान्वित होंगे, नये निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, स्टार्टअप उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा एवं नये रोजगार सृजित होंगे। यह एक प्रमुख सुधार है।

ग) बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जन उपयोगिता (विवादों का निपटारा) विधेयक पेश किया जायेगा और पारदर्शिता से समझौता किये बगैर पीपीपी करारों पर नये सिरे से बातचीत के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

घ) एफडीआई नीति में बदलाव।

ड) किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य पदार्थों के विपणन में एफआईपीबी के जरिए शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जाएगी। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ नए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

च) रणनीतिक विनिवेश के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है और उनकी जल्द ही घोषणा की जाएगी।

छ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निजी इकाइयों का नई परियोजनाओं में निवेश के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से विनिवेश किया जा सकता है।

ज) वित्तीय क्षेत्र में वित्तीशय कंपनियों के वियोजन पर एक व्यापक कोड़ को अधिनियमित किया जाएगा। बैंक दिवालिया और दिवालियापन कानून के साथ इस कोड़ से बड़ा क्रमबद्ध खाली स्थान की भरपाई होगी। यह एक बड़ा सुधार करने वाला कदम है।

झ) परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए सारफेसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इससे बैंक को विवादित परिसंपत्तियों से निपटने में मदद मिलेगी।

ट) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों - (ए) सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनः पूंजीकरण, (बी) सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की मजबूती के लिए रोड़ मैप की घोषणा की जाएगी, (सी) आईडीबीआई बैंक में सरकार की इक्विटी को ४६ प्रतिशत को घटाने पर विचार, (डी)

न्यायालय के मामलों की कम्प्युटरीकृत प्रोसेसिंग के साथ डीआरटी को मजबूत किया जाएगा।

ठ) पारदर्शिता, जवाबदेही और निपुणता में सुधार लाने के लिए सामान्य बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा।

ड) गैर-कानूनी जमावर्ती योजनाओं से निपटने के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून तैयार किया जाएगा।

१४. राज्यों और जिलों को जोड़ने के लिए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का शुभारंभ किया जाएगा।

१५. वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीदारी के लिए डीजीएसएंडडी द्वारा प्रौद्योगिकीजन्य मंच स्थापित किया जाएगा। इससे पारदर्शिता और निपुणता में सुधार के साथ-साथ खरीदारी की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।

१६. वित्तीय विधा :

क) वर्ष २०१६-१७ में वित्तीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का ३.५ प्रतिशत।

ख) एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति का गठन

ग) २०१७-१८ से गैर-योजना वर्गीकरण को हटाना

घ) केन्द्रीय योजना स्कीमों को युक्तिसंगत बनाना। केन्द्रीय योजना के तहत १५०० से ज्यादा स्कीमों को तकरीबन ३०० केन्द्रीय क्षेत्र और ३० केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पुनर्गठित किया गया है।

(स्रोतः इंटरनेट)

दैनिक जागरण में प्रकाशित लेख

गांवों की समृद्धि का संकल्प

● नरेंद्र सिंह तोमर

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया है वह सकारात्मक, विकासपरक और संतुलित है। उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारतीय परिदृश्य के उन सर्वाधिक महत्वरपूर्ण किंतु अभी तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों, वर्गो और पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो देश के संतुलित आर्थिक विकास और जन-कल्याण के लिए बेहद जरूरी हैं। इसे अगर, गांवों, गरीबों और किसानों की समृद्धि का बजट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुखद और महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राजग सरकार देश की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत बनाए रखने में कामयाब रही है। इसका जीता-जागता सबूत यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्लोबल इकोनह्मी के मंदी के माहौल में भारत को एक प्रकाश स्तंभ बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद रही है कि राजग सरकार को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी, जिसमें विकास दर में कमी, कमरतोड़ महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार की खराब स्थिति और निवेशकों में विश्वास की कमी जैसी गंभीर चुनौतियां मुंह बाये खड़ी थीं।

अगर राजग सरकार के लगभग २१ महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षो के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ६.३ प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर ७.६ प्रतिशत हो गई है। मुद्रास्फीति ९.४ प्रतिशत के स्तर से घटकर ५.४ प्रतिशत रह गई है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार ने यह उपलब्धि लगातार दो वर्षो के दौरान मह्नसून की बारिश में १३ प्रतिशत की कमी के बावजूद हासिल की है। १अच्छी बात यह है कि सरकार ने अपना रोड मैप नहीं बदला है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए धन आवंटन में वृद्धि की है। बजट में आधारभूत ढांचे और कृषि पर होने वाले निवेश में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है।

पिछले लगभग दो साल से मानसून ने किसानों का साथ नहीं दिया है। इसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी कि सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान दे। बजट का अध्ययन और विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि वित्तमंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण बाजार की स्थिति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणा की गई है कि अगले पांच वर्षो के दौरान किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। वित्तमंत्री का बजटीय दृष्टिकोण नौ प्रमुख स्तंभों पर आधारित है और यह महज आमदनी और खर्च का ब्यौरा भर नहीं है। उन्होंने जिन नौ स्तंभों का जिक्र किया है उसमें कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, रोजगार और हुनर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। १कृषि के अंतर्गत जिन बातों की चर्चा वित्तमंत्री ने की है उनमें सिंचाई, जमीन की उपज, मृदा स्वास्थ्य

की देखभाल, कृषि का बाजार से संबंध और जैविक खेती की बातें शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा पर भी बल दिया गया है और इसके लिए ३८ हजार ५०० करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। देश बार-बार सूखे का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर नदियों का विशाल संसाधन होने के बावजूद सभी खेतों तक पानी पहुंचाने में अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली कृषि इंद्र देवता की कृपा पर टिकी रहती है। इसे दृष्टि में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मजबूत बनाया गया है और इसे मिशन मोड में क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत साढ़े २८ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। बजट में दालों का उत्पादन बढ़ाने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन के लिए ५०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसानों की उपज के लिए प्रभावी बाजार व्यवस्था का न होना शुरुआत से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ी चुनौती रही है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए बाजारों की सुलभता बहुत आवश्यक है। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार एकीकृत कृषि विपणन योजना लागू कर रही है, जिसमें साझा ई-मार्केट मंच की परिकल्पना की गई है। १सरकार ने वर्ष २०१६-१७ के आम बजट में एक महत्वापूर्ण संकल्प यह भी लिया है कि एक मई, २०१८ तक दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। यह लक्ष्य हासिल हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ डिजिटल इंडिया स्कीम ला रही है, बल्कि उसने किसानों के ई-प्लेटफार्म और स्वास्थ्य सेवा योजना के अलावा ग्राम स्वराज योजना के लिए ६५५ करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। अगर डिजिटल इंडिया स्कीम का क्रियान्वयन सुचारु तरीके से होता है तो गांवों के विकास में पंख लग सकते हैं। सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा के लिए ५५०० करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

देश भर के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए बजट में विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई है। इन सभी योजनाओं और उपायों से स्पष्ट होता है कि गांव के लोगों और किसानों की समृद्धि के लिए सरकार उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रभावी बाजार उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। उन्हें अभी तक अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के माध्यम से उन्हें लाभदायक बाजार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्ण निष्ठा, दृढ़-निश्चय, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं और वायदों पर खरी उतरेगी तथा देश की जनता की उम्मीदें पूरी होंगी।

Key Features of Budget 2016-2017

INTRODUCTION

- Growth of Economy accelerated to 7.6% in 2015-16.
- India hailed as a 'bright spot' amidst a slowing global economy by IMF. Robust growth achieved despite very unfavourable global conditions and twoconsecutive years shortfall in monsoon by 13%
- Foreign exchange reserves touched highest ever level of about 350 billion US dollars.
- Despite increased devolution to States by 55% as a result of the 14th Finance Commission award, plan expenditure increased at RE stage in 2015-16– in contrast to earlier years.

CHALLENGES IN 2016-17

- Risks of further global slowdown and turbulence.
- Additional fiscal burden due to 7th Central Pay Commission recommendations and OROP.

ROADMAP&PRIORITIES

- 'Transform India' to have a significant impact on economy and lives of people.
- Government to focus on– ensuring macro-economic stability and prudent fiscal management. boosting on domestic demand continuing with the pace of economic reforms and policy initiatives to change the lives of our people for the better.
- Focus on enhancing expenditure in priority areas of - farm and rural sector, social sector, infrastructure sector employment generation and recapitalisation of the banks.

FOCUS ON VULNERABLE SECTIONS THROUGH:

- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
- New health insurance scheme to protect against hospitalisation expenditure
- facility of cooking gas connection for BPL families.
- Continue with the ongoing reform programme and ensure passage of the Goods and Service Tax bill and Insolvency and Bankruptcy law Undertake

important reforms by: 1) *giving a statutory backing to AADHAR platform to ensure benefits reach the deserving. 2) Freeing the transport sector fromconstraints and restrictions. 3) incentivising gas discovery and exploration by providing calibrated marketing freedom. 4). Eactment of a comprehensive law to deal with resolution of financial firms provide legal framework for dispute resolution and re-negotiationsin PPP 5). Projects and public utility contracts. 6). Undertake important banking sector reforms and public listing of general insurance companies undertake significant changes in FDI policy.*

AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

अब गांवों की बारी

देश का आम बजट 2016-17 पेश हो चुका है। लोग अपने-अपने हिसाब से इसका फलाफल निकालने में जुटे हैं। राजनीतिक रुझान के हिसाब से उम्मीदों और आशंकाओं का दौर जारी है। इन सबके बीच अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि यह बजट गांव, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के लिए जाना जा सकता है। उनके अनुसार 25 साल पहले 1991 में पेश हुए देश के आम बजट में तमाम प्रावधानों द्वारा उदारीकरण के तहत देश के बाजारों को मुक्त किया गया था। अब गांवों की बारी आई है।

बजट 2016-17 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती-किसानी के बदलने के लिए संतुलित प्रावधान किए गए हैं। काफी समय से आम बजट में तिरस्कार झेल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षमता को नरेंद्र मोदी सरकार ने बखूबी पहचाना है। लोग भले ही सरकार के गांव केंद्रित बजट पेश करने को सूटबूट की सरकार होने के आरोप को धोने की बात कह रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि इस आम बजट में देश की खेती-किसानी की दुश्वारियों, गरीबी, बेरोजगारी, सिंचाई और संसाधनों की जकड़ी बेड़ियां दूर की गई हैं। एक तरह से कहें तो इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बजट के माध्यम से मुक्त करने का प्रयास किया गया है।

देश के अधिकांश शहरी बाजारों की मांग संतृप्त हो चुकी है या होने के करीब है। ऐसे में गांव ही अब रोशनी की किरण बने हैं। अगर गांव के लोग सक्षम होंगे तो मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को दोहरे अंक में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी सरकार ने अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने के अपने एक निशाने से कई लक्ष्य साधे हैं। गांवों की सूरत बदलेगी तो शहरों की सीरत सुधरेगी, उनका दबाव कम होगा। ग्रामीणों का भला होगा तो अर्थव्यवस्था भी कुलांचे भरेगी। तभी भारत महाशक्ति बनेगा। ऐसे में ग्रामीण लोगों और उनकी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित बजट की पड़ताल आज सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

खुली तिजोरी

आर्थिक विकास के क्रम में हमेशा से उपेक्षित रहे कृषि क्षेत्र को मुफलिसी से उबारने के उद्देश्य से बजट 2016-17 में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से एक ओर जहां उत्पादन बढ़ाने पर जोर है तो वहीं दूसरी ओर विपणन प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने की कवायद।

आवंटन में वृद्धि

87,765 करोड़ रुपये
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बजटीय प्रावधान। पिछले बजट से 22 फीसद अधिक

47,912 करोड़ रुपये
सिंचाई की दिक्कत दूर करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन। पिछले साल के मुकाबले 84 फीसद अधिक

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 2016 के बजट में 87,765 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 22 फीसद अधिक है। वहीं कृषि, किसान कल्याण और सिंचाई के लिए बजट में 47,912 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस क्षेत्र की हालत सुधारने के लिए किया गया यह आवंटन अब तक का सबसे अधिक है और पिछले वर्ष की तुलना में 84 फीसद ज्यादा।

सिंचाई फंड

मानसून की मार झेल रहे कृषि के लिहाज से प्रमुख क्षेत्रों में बेहतरीन उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार नाबार्ड में सिंचाई फंड बनाएगी। यह फंड शुरुआत में 20,000 करोड़ रुपये की राशि से तैयार किया जाएगा। भूजल स्रोतों के प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित है। साथ ही आगामी वित्त वर्ष कृषि लोन का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रखा गया है जबकि पिछले वित्त वर्ष यह 8.5 लाख करोड़ था। वहीं फसल बीमा के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मूल्य स्थिरता कोष में इजाफा

सामान्य से कम मानसून के चलते घरेलू बाजार में दाल की बढ़ी कीमतों ने आम लोगों और सरकार को बेहद परेशान किया। रही सही कसर कालाबाजारी करने वालों ने पूरी कर दी। आगामी वित्त वर्ष में इस तरह की समस्या न आए इसके मूल्य स्थिरता कोष को बढ़ाकर 900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 में इस मद में सरकार ने 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। कोष के इस्तेमाल से न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) पर दालों की खरीद की जाएगी जिससे इनका बफर स्टॉक बनाया जा सके। इसके माध्यम से सरकार बाजार में हस्तक्षेप कर घरेलू बाजार में दालों के मूल्य को नियंत्रित करेगी।

डेयरी उत्पादन बढ़ाने की स्कीमें

ग्रामीण इलाकों में डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लांच की गई हैं। पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य, ई-पशुधन हाट और देसी नस्लों के पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए नेशनल जिनोमिक सेंटर फॉर आइडीजिनस ब्रीड्स का प्रावधान किया गया। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना का भी प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट भी प्रस्तावित है। डेयरी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस मद में 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास

पैदावार बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के अंतर्गत मार्च 2017 तक 14 करोड़ खेतों को शामिल करने की तैयारी है। मृदा और बीज की जांच के लिए अगले तीन वर्षों में फर्टिलाइजर कंपनियां इन इलाकों में अपने मॉडल रीटेल आउटलेट शुरू करेंगी।

कृषि किसान सेस

बदहाल कृषि की हालत सुधारने के लिए एक जून से सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 फीसद के कृषि किसान सेस लगाया जाएगा। कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही सरकार एकीकृत कृषि विपणन स्कीम और ई-प्लेटफॉर्म ला रही है। इससे किसान आसानी से अनाज, सब्जियां, फल जैसे उत्पाद बाजारों तक पहुंचा पाएंगे।

courtsy: dainik jagran

- Allocation for Agriculture and Farmers' welfare is '35,984 crore.
- 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana' to be implemented in mission mode.
- 28.5 lakh hectares will be brought under irrigation.
- Implementation of 89 irrigation projects under AIBP, which are languishingfor a long time, will be fast tracked.
- A dedicated Long Term Irrigation Fund will be created in NABARD with an initial corpus of about ' 20,000 crore.
- Programme for sustainable management of ground water resources with an estimated cost of ' 6,000 crore will be implemented through multilateral funding.
- 5 lakh farm ponds and dug wells in rain fed areas and 10 lakh compost pits for production of organic manure will be taken up under MGNREGA.
- Soil Health Card scheme will cover all 14 crore farm holdings by March 2017.
- 2,000 model retail outlets of Fertilizer companies will be provided with soil and seed testing facilities during the next three years.
- Promote organic farming through 'Parmparagat Krishi Vikas Yojana' and 'Organic Value Chain Development in North East Region'.
- Unified Agricultural Marketing ePlatform to provide a common emarket platform for wholesale markets.

अमीरों से लिया, अन्नदाता को दिया

एक करोड़ रुपये से अधिक आय पर सरचार्ज 12 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2016-17 में अमीरों से अधिकाधिक टैक्स वसूलकर सीधे अन्नदाता को मदद देने के राजकोषीय नीति के नए दौर की शुरुआत की। जेटली ने एक करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले लोगों पर मौजूदा 12 फीसद सरचार्ज को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और 10 लाख रुपये से अधिक लाभांश पाने वालों पर 10 फीसद की दर से टैक्स वसूलने की घोषणा की। खास बात यह है कि किसानों के कल्याण और गांवों के विकास के लिए धनराशि जुटाने को वित्त मंत्री ने कालाधन का खुलासा करने वालों पर 7.5 प्रतिशत कृषि कल्याण सरचार्ज वसूलने और करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण सेस लगाने का ऐलान भी किया।

मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए जेटली ने गांवों और किसानों के लिए धन जुटाने को धनाढ्य वर्ग से अधिकाधिक टैक्स वसूलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने दस लाख रुपये से अधिक की लग्जरी कार और दो लाख रुपये से ज्यादा के सामान की खरीद पर एक फीसद की दर से स्रोत पर टैक्स (टीसीएस) लगाने की घोषणा भी की। हालांकि किसानों को एक फार्म भरना होगा। इससे उन पर टीसीएस नहीं लगेगा। इस टैक्स का मकसद न सिर्फ अमीरों से अधिक कर वसूलना है बल्कि कर चोरी करने वाले लोगों को भी पकड़ना है। वित्त मंत्री ने साल में 10 लाख रुपये से अधिक लाभांश पाने वाले व्यक्ति और कंपनियों पर अतिरिक्त राशि का 10 फीसद टैक्स के रूप में वसूलने की भी घोषणा की। यह टैक्स मौजूदा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से अलग होगा। उन्होंने 'ऑप्संस' के मामले में भी सीक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की दर 0.017 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आय वाले धनाढ्य लोगों पर सरचार्ज 12 फीसद से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया। जेटली ने पिछले साल भी इस सरचार्ज में दो प्रतिशत वृद्धि की थी। वित्त मंत्री ने सभी करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण सेस लगाने की घोषणा भी की। मानसून की मार झेल रही खेती को संकट से उबारने के लिए जेटली ने पहली बार कृषि कल्याण सेस लगाने की घोषणा की। कृषि कल्याण सेस एक जून 2016 से लागू होगा। वित्त वर्ष 2016-17 में इससे 5000 करोड़ जुटाने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कालेधन का खुलासा करने वाले लोगों पर भी 7.5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण सरचार्ज वसूलने की घोषणा की। इसका इस्तेमाल किसानों और गांवों के विकास के लिए किया जाएगा।

- लग्जरी कार और दो लाख रुपये की खरीद पर लगेगा एक फीसद टीसीएस
- किसान कल्याण के लिए सेवाओं पर पहली बार 0.5 फीसद कृषि कल्याण सेस
- कालेधन के खुलासे पर देना होगा 7.5 प्रतिशत कृषि कल्याण सरचार्ज

नए कल-कारखानों को देने होंगे कम टैक्स

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कॉरपोरेट कर की दर में चरणबद्ध तरीके से कटौती की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने आम में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अहम घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि एक मार्च 2016 या उसके बाद निगमित होने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर अब मात्र 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स और अधिभार तथा उपकर की दर से टैक्स देने का विकल्प उपलब्ध होगा। हालांकि ऐसा करने पर उन्हें लाभ संबद्ध या निवेश संबद्ध कटौतियों या निवेश छूट और त्वरित अवमूल्यन का लाभ नहीं मिलेगा।

वित्त मंत्री ने उद्योग जगत को कई कर प्रोत्साहन भी दिए। उन्होंने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहनों का एलान किया। जेटली ने कहा कि जिन कंपनियों का टर्नओवर मार्च 2015 की समाप्ति पर 3 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है उन पर भी कॉरपोरेट कर की दर 29 प्रतिशत तथा अधिभार और उपकर लागू होगा। जेटली ने कहा,स्टार्ट अप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं इसलिए सरकार उन्हें पांच वर्षों में से तीन वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर शत प्रतिशत कर कटौती का लाभ देगी।

- Allocation under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana increased to ' 19,000 crore. Will connect remaining 65,000 eligible habitations by 2019.
- To reduce the burden of loan repayment on farmers, a provision of ' 15,000 crore has been made in the BE 2016-17 towards interest subvention.
- Allocation under Prime Minister Fasal Bima Yojana'5,500 crore.
- 850 crore for four dairying projects - 'Pashudhan Sanjivani', 'Nakul Swasthya Patra', 'E-Pashudhan Haat' and National Genomic Centre for indigenous breeds.

RURAL SECTOR

- Allocation for rural sector-'87,765 crore.
- 2.87 lakh crore will be given as Grant in Aid to Gram Panchayats and Municipalities as per the recommendations of the 14th Finance Commission.
- Every block under drought and rural distress will be taken up as an intensive Block under theDeen Dayal AntyodayaMission A sum of'38,500 crore allocated for MGNREGS.

युवा भारत को सशक्त करने वाला बजट

विशेषज्ञ टिप्पणी

राजीव चंद्रशेखर, सांसद

- बजट दस्तावेज से और ज्यादा स्पष्ट हो रहा पीएम मोदी का आर्थिक दर्शन
- दर्शा रहा है कि युवा व उद्यमी ही बदल सकते हैं देश की तकदीर

गांवों में बहेगी डिजिटल बयार

छह लाख ग्रामीण परिवार तीन साल के भीतर बनेंगे डिजिटल साक्षर

150 करोड़ भूमि अभिलेख के लिए

सूखे से हलकान गांवों के जख्म पर लगाया मरहम

त्रिशंकु बने कस्बों व गांवों का होगा भाग्योदय

विकास का इंजन

ग्रामीण क्षेत्र विकास का इंजन है। सबसे ज्यादा लोग यहां रहते हैं। सबसे ज्यादा उपभोक्ता यहां हैं। इनके जीवन स्तर और कल्याण में अगर सुधार होता है तो देश में मांग बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तमाम क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ता है जिससे अंततः अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि करती है।

100 करोड़
देश में कुल उपभोक्ता

75 करोड़
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ता

50 फीसद
कुल राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र की हिस्सेदारी

425 अरब डॉलर
ग्रामीण उपभोक्ता बाजार का 2008-09 के दौरान राजस्व

266 अरब डॉलर
ग्रामीण उपभोक्ता बाजार का 2007-08 के दौरान राजस्व

63 फीसद
ग्रामीण उपभोक्ता बाजार की कमाई में एक साल में हुई वृद्धि

बढ़ती क्रय शक्ति

ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों की संख्या 22 फीसद से 46 फीसद हो चुकी है। एफएमसीजी पर औसत खर्च शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी भी सूचनाएं है कि एलजी, हीरो और नोकिया के कुल राजस्व में 40 फीसद हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्र की है। हिंदुस्तान यूनीलीवर के लिए यह 50 फीसद है।

बैंक क्रेडिट में वृद्धि

किसी आर्थिक गतिविधि की नाड़ी मापने के लिए जिन जरूरी मानकों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से बैंक क्रेडिट भी एक है। मार्च 2014 से दिसंबर 2014 के बीच ग्रामीण और अर्द्ध शहरी केंद्रों की क्रेडिट वृद्धि क्रमशः 9.8 और 8.5 फीसद रही। शहरों और मेट्रोपालिटन केंद्रों में इसकी तुलना में 4.3 और 2.3 फीसद की सुस्त रफ्तार रही। ग्रामीण इलाकों का कुल ऋण मार्च 2014 में 4.22 लाख करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2014 में 4.63 लाख करोड़ हो गया। इसी समयावधि के दौरान ग्रामीण भारत में कुल बैंक खाते 3.23 करोड़ से बढ़कर 3.4 करोड़ हो गए। इसकी तुलना में शहरों में कर्ज लेने वालों के खाते में 10.34 लाख की वृद्धि हुई और ये 1.2 करोड़ का आंकड़ा छुआ।

- 300 Rurban Clusters will be developed under the Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission.
- 100% village electrification by 1st May, 2018.
- District Level Committees under Chairmanship of senior most Lok Sabha MP from the district for monitoring and implementation of designated Central Sector and Centrally Sponsored Schemes.
- Priority allocation from Centrally Sponsored Schemes to be made to reward villages that have become free from open defecation.
- A new Digital Literacy Mission Scheme for rural India to cover around 6 crore additional household within the next 3 years.
- National Land Record Modernisation Programme has been revamped. New schemeRashtriya Gram Swaraj Abhiyanproposed with allocation of'655 crore.

घर-घर में रसोई गैस महिलाएं होंगी स्वस्थ

75 लाख परिवारों ने छोड़ी है रसोई गैस सब्सिडी

27000 करोड़ रुपये हुई घटकर पेट्रोलियम सब्सिडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अपील से आगे बढ़कर अब सरकार क्रियान्वयन के स्तर पर उतर आई है। सरकार ने बजट में चूल्हा फूंकने वाली गरीब महिलाओं की सुध ली है। इसके तहत अगले तीन वर्षों में पांच करोड़ बीपीएल घरों में रसोई गैस पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार महिला सदस्यों के नाम एलपीजी कनेक्शन देने का विशाल मिशन शुरू करेगी। इस वर्ग को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की शुरुआती लागत पूरी करने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सरकार के पास इसके लिए पूरा आधार भी तैयार है। सरकार ने पहले ही मन बना लिया है कि सब्सिडी वाले कनेक्शन केवल उन्हें ही मिलेगी जो इस योग्य हैं। इसी रुख के कारण पेट्रोलियम पर सब्सिडी का बोझ 1.30 लाख करोड़ से घटकर 27 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। इस वर्ष करीब डेढ़ करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिलेगा। योजना कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी ताकि पांच करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

• दो हजार करोड़ रुपये का आवंटन

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की अपील पर अब तक 75 लाख परिवारों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी है। खुद प्रधानमंत्री रेडियो और टीवी के जरिए यह अपील करते रहे हैं कि समर्थ लोग सब्सिडी छोड़ें ताकि उन घरों में कनेक्शन दिया जा सके जिनकी आंखें चूल्हे के धुओं से सूनी पड़ती जा रही हैं। अध्ययन बताते हैं कि एक चूल्हे की भट्ठी चार सौ सिगरेट जलने के बराबर होती है। सरकार की इस योजना से न सिर्फ महिलाओं का सशक्तीकरण होगा बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी।

SOCIAL SECTOR INCLUDING HEALTH CARE

गरीबों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा

● अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन इंडेक्स पर ऊपर जाने से रोकती रही है उपेक्षा

आशुतोष झा, नई दिल्ली

11 करोड़ सदस्य बनाने के बावजूद पिछले दो चुनावों में मुंह की खा चुकी भाजपा सरकार का ध्यान 'अंत्योदय' पर केंद्रित हो गया है। बजट में सरकार का यह नजरिया स्पष्ट हो गया है कि गरीबी रेखा पर खड़ी लगभग 30 फीसद आबादी को स्वस्थ रखकर ही देश खुशहाल होगा। सरकार भी सफल होगी और व्यक्तिगत राजनीति भी चमकेगी। लिहाजा किसानों को फसल बीमा देने के बाद अब सरकार ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने के साथ-साथ सस्ती दवाओं, हर जिले में डायलिसिस सेवा जैसी सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। लगभग पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला कर सरकार ने उनके घरों में उपस्थिति सुनिश्चित की है।

ऐसे वक्त में जबकि भारत में मेडिकल बीमा का फीसद बहुत कम है, सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक लाख रुपये की स्वास्थ्य योजना लाने का महत्वाकांक्षी फैसला लिया है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में एक लाख रुपये के अलावा 30 हजार रुपये का अतिरिक्त बीमा होगा। सीधे तौर पर तो यह राजनीति से जुड़ा फैसला लग सकता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस योजना का दूरगामी असर दूसरी योजनाओं पर भी दिखेगा। गौरतलब है कि परिवार में अचानक आने वाली बीमारियों के कारण ही कई गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ऐसे परिवारों की संख्या लाखों में है। इस योजना को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि किडनी से जुड़ी बीमारी और अहम दवाइयों की उपलब्धता को लेकर सरकार ने बजट में ही प्रावधान कर दिया है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत अगले वित्त वर्ष में तीन हजार स्टोर खोले जाएंगे, जहां सस्ते दामों में दवाइयां मिलेंगी। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग सवा दो लाख किडनी के नए रोगियों की संख्या जुड़ जाती है, जिन्हें डायलिसिस की जरूरत होती है। सरकार ने दूरदृष्टि के साथ इस रोग के इलाज के साथ-साथ रोजगार का माध्यम ढूंढ लिया है। पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम हर जिला स्वास्थ्य सेंटर पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराएगा। जाहिर तौर पर यह उन गरीबों के लिए खास उपयोगी होगा जो इस पर आने वाले सालाना लगभग तीन लाख रुपये का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। ध्यान रहे कि समाज के इस वर्ग की अनदेखी देश को अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन इंडेक्स पर ऊपर जाने से रोकता रहा है। राजनीति के लिहाज से भी यह वह वर्ग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो स्वस्थ हुआ तो समृद्ध आधार दे सकता है। अगर समय रहते योजनाएं जमीन पर उतरी तो अगले साल होने वाले अहम राज्यों में इसका असर दिख सकता है।

2.25 लाख लोग हर साल हो जाते हैं किडनी के मरीज

3000 स्टोर खोले जाएंगे जहां सस्ते दामों में दवाइयां मिलेंगी

1,00,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा गरीब परिवारों को मिलेगा

- Allocation for social sector including education and health care – '1,51,581 crore.
- 2,000 crore allocated for initial cost of providing LPG connections to BPL families.
- New health protection scheme will provide health cover up to ' One lakh per family.
- For senior citizens an additional top-up package up to' 30,000 will be provided.
- 3,000 Stores under Prime Minister's Jan Aushadhi Yojana will be opened during 2016-17.
- National Dialysis Services Programme' to be started under National Health Mission through PPP mode.
- "Stand Up India Scheme" to facilitate at least two projects per bank branch.
- This will benefit at least 2.5 lakh entrepreneurs.
- National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub to be set up in partnership with industry associations.
- Allocation of ' 100 crore each for celebrating the Birth Centenary of Pandit Deen Dayal Upadhyay and the 350th Birth Anniversary of Guru Gobind Singh.

EDUCATION, SKILLS AND JOB CREATION

- 62 newNavodaya Vidyalayaswill be opened.
- Sarva Shiksha Abhiyanto increasing focus on quality of education Regulatory architecture to be provided to ten public and ten private institutions to emerge as world-class Teaching and Research Institutions.
- Higher Education Financing Agency to be set-up with initial capital base of'1000 Crores.
- Digital Depository for School Leaving Certificates, College Degrees, Academic Awards and Mark sheets to be set-up.

खुलेंगे 62 नए नवोदय विद्यालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बेहतर और विश्वस्तरीय शिक्षा को सरकार ने अपना ध्येय बनाया है। यही कारण है कि 2001 में शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान के लिए इस साल बड़ी राशि का आवंटन किया गया है। 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। विश्वस्तरीय रैंकिंग वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी दूर करने के प्रयास होंगे। इसके तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में ऐसे दस-दस संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार विधेयक लाकर इसका प्रबंध करेगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं में आम छात्र को विश्वस्तरीय शिक्षा कम खर्च में मिल सके इस क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी स्थापित करने का फैसला भी किया है। यह एजेंसी संस्थानों के संपूर्ण ढांचागत विकास को सुनिश्चित करेगी।

बुनियादी सुविधाओं पर जोर

अगले दो साल में उन 62 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे जहां अभी यह नहीं हैं। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्यक्रम बेहतर करने पर जोर होगा। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं जैसे, बैठने की व्यवस्था से लेकर शौचालय, पैयजल आदि को बढ़ाने पर भी जोर होगा।

डिजिटल स्टोरेज

शैक्षणिक दस्तावेजों के खो जाने पर छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों से मिलने वाले दस्तावेज जैसे डिग्री, प्रमाण-पत्र, उपाधि, परित्याग-पत्र आदि के डिजिटल स्टोरेज का प्रस्ताव दिया है।

स्वच्छ गांव होंगे पुरस्कृत

स्वच्छता अब सिर्फ नारा नहीं होगा। गांवों को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को और गति देने के लिए गांवों के बीच ही प्रतिस्पर्द्धा शुरू करने का निर्णय लिया है। जो गांव खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सोमवार को पेश बजट में गांव और गरीब प्राथमिकता में हैं। खासकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। यह भी जाहिर है कि स्वच्छता के बिना कोई दूसरी योजना पूरी तरह परवान नहीं चढ़ेगी। यही कारण है कि शहरों के बीच चल रही प्रतिस्पर्द्धा की तर्ज पर ही गांवों के बीच भी प्रतिस्पर्द्धा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

DEVELOPMENT

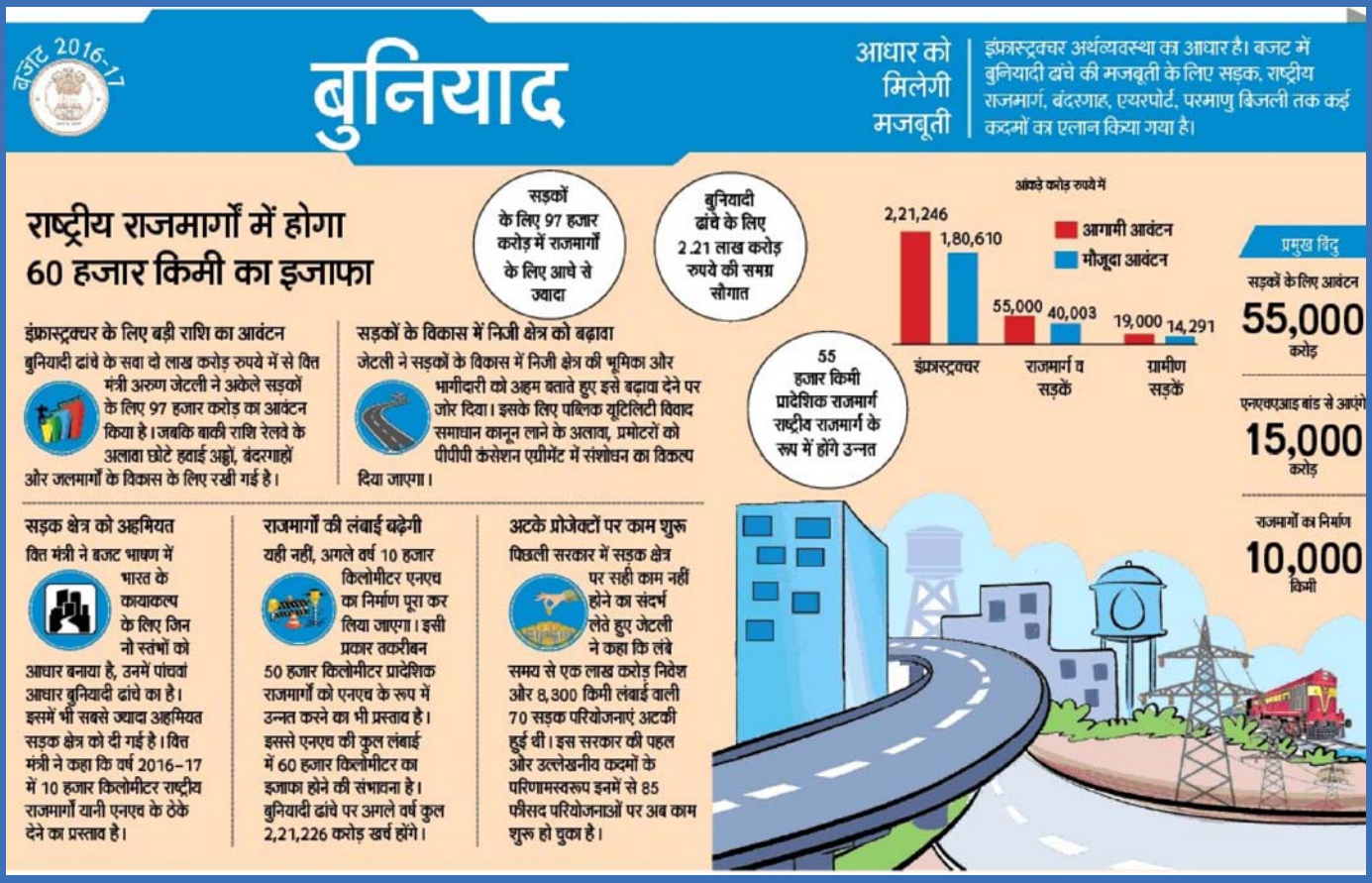

- Allocation for skill development–'1804. crore.
- 1500 Multi Skill Training Institutes to be set-up.
- National Board for Skill Development Certification to be setup in partnership with the industry and academia.
- Entrepreneurship Education and Training through Massive Open Online Courses

JOB CREATION

- GoI will pay contribution of 8.33% for of all new employees enrolling in EPFO for the first three years of their employment. Budget provision of '1000 crore for this scheme.
- Deduction under Section 80JJAA of the Income Tax Act will be available to all assesses who are subject to statutory audit under the Act .
- 100 Model Career Centres to operational by the end of 2016-17 under National Career Service.
- Model Shops and Establishments Bill to be circulated to States.

INFRASTRUCTURE AND INVESTMENT

बजट 2016-17

समर्थ समाज

स्वस्थ जन, खुशहाल भारत

बजट में गांव, खेत-खलिहान, बुजुर्ग, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। गरीबों और दलितों का सशक्तीकरण इसके केंद्र में है। सबको विश्वस्तरीय शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर है।

दलित नौकरी मांगेंगे नहीं, देंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरक्षण के सहारे दलितों के उत्थान की छह दशक पुरानी नीति से आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार अब उन्हें स्वावलंबी उद्यमी बनाने की तैयारी में है। उन्हें नौकरी मांगने वालों की श्रेणी से निकालकर नौकरी देने वालों की श्रेणी में लाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय में विशेष केंद्र भी खोला जाएगा।

दलित राजनीति गर्म है और विपक्ष आरोपों के साथ सरकार पर हावी। ऐसे में सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए ठोस योजना से विपक्षी दलों को भी जवाब दिया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत एससी/एसटी और महिलाओं को नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता मिलती है। इसके तहत बैंक के हर ब्रांच को कम से कम दो उद्यमियों को मदद देनी होगी। इन दलित उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केंद्र खोला जाएगा। यह केंद्र सरकारी खरीद में दलित उद्यमियों के उत्पादों को शामिल करने में सहायता करेगा।

कुशल बनेंगे युवा

कौशल विकास योजना को और व्यापक बनाने व रोजगार से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। अब तक 76 लाख युवा इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। सरकार की कोशिश अगले तीन साल में एक करोड़ अन्य युवाओं का कौशल विकास करना है। युवाओं में कौशल की प्रामाणिकता बनाने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों की मदद से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड बनाया जाएगा। 2200 कॉलेज, 300 स्कूल, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कौशल विकास में मदद करेंगे।

रोजगार देने पर कर छूट

कुशल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का आधार भी तैयार होने लगा है। नए रोजगार देने वाले उद्योगों को अब तीन साल तक उस कर्मचारी का 8.33 फीसद भविष्य निधि नहीं देना होगा। इसका भुगतान सरकार करेगी। यह छूट 15,000 रुपये मासिक आमदनी वाले कर्मचारियों पर ही लागू होगी। इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों को करों में छूट देने का भी प्रावधान है। काउंसलिंग की व्यवस्था भी होगी। इसके लिए पूरे देश में 100 मॉडल कैरियर सेंटर खोले जाएंगे और बाद में उन्हें राज्यों के रोजगार कार्यालयों के राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा।

नए उद्यमियों को प्रोत्साहन

देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। स्टार्ट अप इंडिया के तहत अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक खोले जाने वाले उद्योगों को पांच में से तीन साल तक कर में छूट मिलेगी। कंपनी कानून 2013 में संशोधन कर ऐसी कंपनी को खोलना आसान बनाया जाएगा। सरकार की कोशिश कंपनी का पंजीकरण एक दिन में करने का है।

1700 करोड़ रुपये की लागत से खुलेंगे 1500 कौशल प्रशिक्षण संस्थान

500 करोड़ स्टैंड अप इंडिया को

600 करोड़ स्टार्ट अप इंडिया को

2.5 लाख दलित व महिला उद्यमी होंगे लाभान्वित

01 करोड़ युवाओं का तीन साल में होगा कौशल विकास

- Total investment in the road sector, including PMGSY allocation, would be'97,000 crore during 2016-17.
- India's highest ever kilometres of new highways were awarded in 2015. To approve nearly 10,000 kmsof National Highways in 2016-17.

- Allocation of ' 55,000 crore in the Budget for Roads. Additional ' 15,000 crore to be raised by NHAI through bonds.
- Total outlay for infrastructure-'2,21,246crore.
- Amendments to be made in Motor Vehicles Act to open up the road transport sector in the passenger segment.
- Action plan for revival of unserved and underserved airports to be drawn up in partnership with State Governments.
- To provide calibrated marketing freedom in order to incentivise gas production from deep-water, ultra deep-water and high pressure-high temperature areas.
- Comprehensive plan, spanning next 15 to 20 years, to augment the investment in nuclear power generation to be drawn up. Steps to re-vitalise PPPs:
- Public Utility (Resolution of Disputes) Bill will be introduced during 2016-17.
- Guidelines for renegotiation of PPP Concession Agreements will be issued.?

बंद पड़े 160 हवाई अड्डे होंगे चालू

क्षेत्रीय स्तर पर यातायात बढ़ाने की नई विमानन नीति का मंसूबा होगा पूरा

एयरपोर्ट अथॉरिटी की 10 उपेक्षित हवाई पट्टियों से शुरू होंगी उड़ानें

हवाई किराये हो सकते हैं महंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बजट में नई विमानन नीति की प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुदूर इलाकों को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए बेकार पड़े 160 छोटे हवाई अड्डों और दस हवाई पट्टियों का राज्यों के सहयोग से विकास किया जाएगा।

वित्तमंत्री के मुताबिक, देश में ऐसे 160 छोटे हवाई अड्डे हैं, जिनका बहुत कम या बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा। ये हवाई अड्डे राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। केंद्र इनमें से प्रत्येक हवाई अड्डे में 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपये तक का निवेश कर इन्हें चालू कराना चाहता है। इनमें से कुछ हवाई अड्डे राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में विकसित किए जाएंगे।

इसी तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया (एएआइ) की 25 में से दस हवाई पट्टियां ऐसी हैं, जिनका प्रायः न के बराबर उपयोग होता है। इन्हें भी विकसित कर उपयोग के लायक बनाया जाएगा। मसौदा विमानन नीति में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि छोटे नगरों के लोगों को भी उचित कीमत पर हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके। क्षेत्रीय यातायात की सीमित सुविधा तथा लागत अधिक है।

बजट में एटीएफ पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने के बाद हवाई किरायों में बढ़ोतरी के आसार बन गए हैं। वित्त मंत्री ने विमान ईंधन (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क को आठ से बढ़ाकर 14 फीसद करने की घोषणा की। इससे केवल क्षेत्रीय उड़ाने भरने वाली शेड्यूल्ड एयरलाइनों को छूट मिलेगी। उनके एटीएफ पर यह ड्यूटी आठ फीसद ही रहेगी।

- New credit rating system for infrastructure projects to be introduced Reforms in FDI policy in the areas of Insurance and Pension, Asset Reconstruction Companies, Stock Exchanges.
- 100% FDI to be allowed through FIPB route in marketing of food products produced and manufactured in India.
- A new policy for management of Government investment in Public Sector Enterprises, including disinvestment and strategic sale, approved.

RELIEF TO SMALL TAX PAYERS

- Raise the ceiling of tax rebate under section 87A from '2000 to '5000 to lessen tax burden on individuals with incomeupto'5 laks.
- Increase the limit of deduction of rent paid under section 80GG from '24000 per annum to '60000, to provide relief to those who live in rented houses.

छोटे करदाताओं को दोहरी राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपेक्षानुरूप कदम उठाते हुए बजट में आयकर से छूट की सीमा तो नहीं बढ़ाई, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत देने में जरूर सफल रहे। उन्होंने दो करोड़ छोटे करदाताओं को दोहरी टैक्स राहत भी दी जिससे पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों को सालभर में 6600 रुपये का लाभ होगा।

6600
रुपये का लाभ वित्त मंत्री के उपायों से होगा

उन्होंने कहा कि कहा कि ऐसे करदाताओं को अब आयकर कानून की धारा 87ए के तहत कर में 5000 रुपये की छूट मिल सकेगी। अब तक यह सीमा केवल दो हजार रुपये थी।

वित्त मंत्री ने उन करदाताओं को भी राहत दी जिनके पास अपना मकान नहीं है और जो किराये के मकान में रहते हैं, जिन्हें अपने इनके नियोक्ता से आवास का भत्ता भी नहीं मिलता है वैसे करदाता अब आयकर कानून की धारा 80जीजी के तहत 60,000 रुपये सालाना कर कटौती का लाभ ले सकेंगे। अब तक यह सीमा मात्र 24,000 रुपये सालाना थी।

नहीं बढ़ाई आयकर से छूट की सीमा

वित्त मंत्री ने आयकर से छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये पर ही बरकरार रखी। आर्थिक समीक्षा 2015-16 में भी सरकार को कर से छूट की सीमा न बढ़ाने की सलाह दी गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका पांडेय का कहना है कि वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों में संतुलन बनाते हुए लोकलुभावन घोषणाओं से बचने की कोशिश की है। धनाढ्य लोगों पर कर का बोझ बढ़ेगा वहीं आम लोगों तथा छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री ने आयकर कानून की धारा 44एडी के तहत प्रीज्युम्टिव टैक्स योजना के तहत आने वाले एमएसएमई कारोबारियों के लिए मौजूदा एक करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की घोषणा भी की है।

व्यक्तिगत आयकर का नया स्लैब इस प्रकार है

आय सीमा	कर की दर प्रतिशत में
2,50,000 रुपये तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000	10
5,00,000 से 10,00,000	20
10,00,000 रुपये से अधिक	30

साठ से 80 वर्ष की आयु के लोगों के लिए	
3,00,000 रुपये तक	शून्य
3,00,000 से 5,00,000	10
5,00,000 से 10,00,000	20
10,00,000 से अधिक	30

अस्सी वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए	
5,00,000 रुपये तक	शून्य
5,00,000 से 10,00,000	20
10,00,000 से अधिक	30
10,00,000 से अधिक	30

राजस्व सचिव हसमुख अढिया का कहना है कि टैक्स में छूट की सीमा दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने से छोटे करदाताओं को तीन हजार रुपये का लाभ होगा। वहीं किराए के एवज में कटौती की सीमा बढ़ाने से करदाताओं को 3600 रुपये का लाभ होगा। इस तरह इन दोनों उपायों से छोटे करदाताओं को 6600 रुपये का लाभ होगा।

BOOST EMPLOYMENT AND GROWTH

- Increase the turnover limit under Presumptive taxation scheme under section 44AD of the Income Tax Act to ' 2 crores to bring big relief to a large number of assesseesin the MSME category.
- Extend the presumptive taxation scheme with profit deemed to be 50%, to professionals with gross receipts up to '50 lakh.
- Phasing outdeductionunderIncomeTax:
- Accelerated depreciation wherever provided in IT Act will be limited to maximum 40% from 1.4.2017.
- Benefit of deductions for Research would be limited to 150% from 1.4.2017 and 100% from 1.4.2020.
- Benefit of section 10AA to new SEZ units will be available to those units which commence activity before 31.3.2020.
- The weighted deduction under section 35CCD for skill development will continue up to 1.4.2020
- **Corporate Taxrate proposals:** New manufacturing companies

incorporated on or after 1.3.2016 to be given an option to be taxed at 25% + surcharge and cess provided they do not claim profit linked or investment linked deductions and do not avail of investment allowance and accelerated depreciation.

- Lower the corporate tax rate for the next financial year for relatively small enterprises i.e companies with turnover not exceeding ' 5 crore (in the financial year ending March 2015), to 29% plus surcharge and cess.
- 100% deduction of profits for 3 out of 5 years for startups setup during April,2016 to March,2019. MAT will apply in such cases.
- 10% rate of tax on income from worldwide exploitation of patents developed and registered in Indiaby a resident.
- Complete pass through of income-tax to securitization trusts including trusts of ARCs.
- Securitisation trusts required to deduct tax at source.
- Period for getting benefit of long term capital gain regime in case of unlisted companies is proposed to be reduced from three to two years. Non-banking financial companies shall be eligible for deduction to the extent of 5% of its income in respect of provision for bad and doubtful debts.
- Determination of residency of foreign company on the basis of Place of Effective Management (POEM) is proposed to be deferred by one year.
- Commitment to implement General Anti Avoidance Rules (GAAR) from 1.4.2017.
- Exemption of service tax on services provided under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana and services provided by Assessing Bodies empanelled by Ministry of Skill Development & Entrepreneurship.
- Exemption of Service tax on general insurance services provided under 'Niramaya' Health Insurance Scheme launched by National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability.
- Basic custom and excise duty on refrigerated containers reduced to 5% and 6%.

MAKE IN INDIA

- Changes in customs and excise duty rates on certain inputs to reduce costs and improve competitiveness of domestic industry in sectors like Information technology hardware, capital goods, defence production, textiles, mineral fuels & mineral oils, chemicals & petrochemicals, paper, paperboard & newsprint, Maintenance repair and overhauling [MRO] of aircrafts and ship repair.

MOVING TOWARDS A PENSIONED SOCIETY

- Withdrawal up to 40% of the corpus at the time of retirement to be tax exempt in the case of National Pension Scheme (NPS). Annuity fund which goes to legal heir will not be taxable.
- In case of superannuation funds and recognized provident funds, including EPF, the same norm of 40% of corpus to be tax free will apply in respect of corpus created out of contributions made on or from 1.4.2016.
- Limit for contribution of employer in recognized Provident and

Superannuation Fund of ' 1.5 lakh per annum for taking tax benefit. Exemption from service tax for Annuity services provided by NPS and Services provided by EPFO to employees.

- Reduce service tax on Single premium Annuity (Insurance) Policies from 3.5% to 1.4% of the premium paid in certain cases.

PROMOTING AFFORDABLE HOUSING

- 100% deduction for profits to an undertaking in housing project for flats upto30 sq. metres in four metro cities and 60 sq. metres in other cities, approved during June 2016 to March 2019 and completed in three years. MAT to apply.
- Deduction for additional interest of '50,000 per annum for loans up to '35 lakh sanctioned in 2016-17 for first time home buyers, where house cost does not exceed '50 lakh.
- Distribution made out of income of SPV to the REITs and INVITs having specified shareholding will not be subjected to Dividend Distribution Tax,

in respect of dividend distributed after the specified date.

- Exemption from service tax on construction of affordable houses up to 60 square metres under any scheme of the Central or State Government including PPP Schemes.
- Extend excise duty exemption, presently available to Concrete Mix manufactured at site for use in construction work to Ready Mix Concrete.

RESOURCE MOBILIZATION FOR AGRICULTURE, RURAL ECONOMY AND CLEAN ENVIRONMENT

- Additional tax at the rate of 10% of gross amount of dividend will be payable by the recipients receiving dividend in excess of ' 10 lakh per annum. k
- Surcharge to be raised from 12% to 15% on persons, other than companies, firms and cooperative societies having income above ' 1 crore.
- Tax to be deducted at source at the rate of 1 % on purchase of luxury cars exceeding value of'ten lakh and purchase of goods and services in cash exceeding'two lakh. Securities Transaction tax in case of 'Options' is

proposed to be increased from .017% to .05%.

- Equalization levy of 6% of gross amount for payment made to nonresidents exceeding'1 lakh a year in case of B2B transactions. Krishi Kalyan Cess, @ 0.5% on all taxable services, w.e.f. 1 June 2016. Proceeds would be exclusively used for financing initiatives for improvement of agriculture and welfare of farmers. Input tax credit of this cess will be available for payment of this cess.
- Infrastructure cess, of 1% on small petrol, LPG, CNG cars, 2.5% on diesel cars of certain capacity and 4% on other higher engine capacity vehicles and SUVs. No credit of this cess will be available nor credit of any other tax or duty be utilized for paying this cess.
- Excise duty of '1% without input tax credit or 12.5% with input tax credit' on articles of jewellery [excluding silver jewellery, other than studded with diamonds and some other precious stones], with a higher exemption and eligibility limits of ` 6 crores and ` 12 crores respectively.
- Excise on readymade garments with retail price of ' 1000 or more raised to 2% without input tax credit or 12.5% with input tax credit.
- Clean Energy Cess' levied on coal, lignite and peat renamed to 'Clean Environment Cess' and rate increased from `200 per tonne to `400 per tonne.
- Excise duties on various tobacco products other than beedi raised by about 10 to 15%.
- Assignment of right to use the spectrum and its transfers has been deducted as a service leviable to service tax and not sale of intangible goods.

(Part of Union Budget 2016-17, taken from finmin.nic.in)

Scan Copy courtesy : Dainik Jagran

Enhanced focus on Higher and Skills Education Welcome!

● **Rohan Joshi**

Union Budget 2016-17 has clearly come out with greater focus on quality of higher education in the country. Handful of new schemes, both for Higher Education and Skill Development, testify government's commitment towards leveraging the demographic dividend of this country. With a meager increase of 1368 crores in school education budget, one may conclude that school education has received lesser attention in terms of new budgetary provisions or schemes in Budget 2016-17. However, Hon Finance Minister's acknowledgement that the quality of school education matters, followed by the announcement that Sarva Shiksha Abhiyan will focus more on quality of education must be welcomed. This is a significant change from previous budget discussions which concentrated largely on building new schools or creating school infrastructure with little to no focus on actual quality of education. One key component in enhancing quality of education is assessments, which do not seem to appear in this year's budget discussion. This is alarming particularly when MHRD, in previous two budgets, even after allocating a small amount (Allocated budget of INR 50 Crore in 2015-16) for assessments has not managed to fully utilize the allotted funds. As the saying goes, what cannot be measured, cannot be improved. It is important to evaluate quality through large scale assessments before resolving to improve it in the months to come through SSA or any of the other institutions.

While it is tempting to call out Hon Finance Minister on his silence on school education through his budget speech, it is important to note that gross budget allocation for education sector has shown marginal increase (INR 1368 crore) from the previous year's revised estimates. This is assuring when seen together with Minister's comment on quality of school education. We hope that the revised focused on quality will also help overcome the challenge of access as reflected by alarming drop-out rates at both elementary and secondary education stages. The challenge in this year's budget is primarily in terms of approach to funds allocation for school education. Looking at the budget allocation for SSA which has increased by approximately 500 crores from the

previous year's revised budget estimates, it is clear that the government has continued with its traditional approach of allocating grants for institutions and not for students. This is alarming when underutilization of Prarambhik Shiksha Kosh followed by inefficient use of the budget (near 80% of the budget spent on teacher salaries) itself have plagued the education system for years.

Over the years Navodaya Vidyalayas have emerged as bright spots in government education system and the announcement this year to create 62 new Navodaya Vidyalayas can be seen as a small token of acknowledgement of the good work that these schools have been doing in delivering quality secondary education.

On Skill education front two announcements stand out this year. First which must be commended is of establishing 300 career support centers. Providing counselling support to students before enrolling them in myriad of skilling programs is a step in the right direction. Second announcement of establishing 1500 multi skilling centers however raises a serious concern. Would these centers be any different from ITIs, which have essentially been the main reason for poor state of employability skills in India?

Overall the establishment of National Board for Skill Development Certification and, the provision of Entrepreneurship Education and Training are welcome moves. In terms of integration of skill education with school education, schemes such as Nai Manzil which focus on providing skill education to children studying in Madarasas need to be scaled up to all schools. While this year's budget has remained silent on this issue, its certainly something to desire for either in one of the future budgets or in the much awaited New Education Policy.

Associate Director, Centre for Civil Society

Rail budget: Improving quality of travel

The Way Ahead

For the unreserved passenger –

- Antyodaya Express unreserved, superfast service.
- Deen Dayalu coaches – unreserved coaches with potable water and higher number of mobile charging points.

For the reserved passenger –

- Humsafar - fully air-conditioned third AC service with an optional service for meals Tejas - will showcase the future of train travel in India. Will operate at speeds of 130
- kmph and above.Will offer onboard services such as entertainment, local cuisine, WiFi, etc. through one service provider for ensuring accountability and improved customer satisfaction Humsafar and Tejas to ensure cost

recovery through tariff and non-tariff measures

- **UDAY -** overnight double-decker, Utkrisht Double-Decker Air-conditioned Yatri Express on the busiest routes, has the potential to increase carrying capacity by almost 40%.
- **Ticketing:** Sale of tickets through hand held terminals; e- ticketing facility to foreign debit/credit cards; bar coded tickets, scanners and access control on a pilot basis. Expansion of Vikalp – train on demand to provide choice of accommodation in specific trains to wait- listed passengers. E-booking of tickets facility on the concessional passes available to journalists; facility of cancellation through the 139 helpline post verification using 'One Time Password' sent on registered phone number, to improve tatkaal services CCTV cameras on windows and periodic audit of PRS website.
- **Cleanliness -'**Clean my Coach' service through SMS, ranking of A1 and A stations based on periodic third party audit and passenger feedback; waste segregation and recycling centres;
- **'Awareness campaigns';** additional 30,000 bio-toilets; providing portable structures with biotoilets at all platforms of select stations for senior citizens, Divyang and women travellers, plan to explore innovative means of providing and maintaining toilets such as advertisement rights, CSR, voluntary support from social organizations.
- **Catering and stalls at stations** -IRCTC to manage catering services in a phased manner;
- explore possibility of making catering services optional, adding 10 more IRCTC operated base kitchens; to build local ownership and empowerment, weightage will be given to district
- domicile holders for commercial licenses at stations.
- **Stoppages:** convert all operational halts into commercial halts for the benefit of the common man.
- **Rail Mitra Sewa:** expanding Sarathi Seva in Konkan Railway to help the old and disabled passengers, strengthening the existing services for enabling passengers to book battery operated cars, porter services, etc. on a paid basis in addition to the existing pick up and drop, and wheel chair services.
- **Measures for Divyang:** all stations under redevelopment accessible by Divyang; to provide at least one Divyang friendly toilet at each platform in A1 class stations during the next financial year and also ensure availability of wheelchairs in sufficient numbers at these stations.

- **Travel Insurance to passengers -** to offer optional travel insurance for rail journeys at the time of booking.
- **Hourly booking of retiring rooms** - will be handed over to IRCTC.
- **Janani sewa:** children's menu items on trains, baby foods, hot milk and hot water would be made available.
- **SMART (Specially Modified Aesthetic Refreshing Travel) Coaches** - design and layout of our coaches to ensure higher carrying capacity and provision of new amenities including automatic doors, bar-code readers, bio-vacuum toilets, water-level indicators, accessible dustbins, ergonomic seating, improved aesthetics, vending machines, entertainment screens, LED lit boards for advertising, PA system.
- **Mobile Apps -** integrate all facilities into two mobile apps dealing with ticketing issues and for receipt and redressal of complaints and suggestions.
- **Improving customer interface-** skilling our front-end staff and those we employ through our ervice providers, information boards in trains enumerating the on-board services and also GPS based digital displays inside coaches to provide real time information regarding upcoming halts. Work underway on installation of a high-tech centralized network of 20,000 screens across 2000 stations for enabling real time flow of information to passengers and also unlock huge advertising potential. All A1 class stations will be manned with duly empowered Station Directors supported by cross functional teams; to make one person accountable for all facilities on trains.
- **Pilgrimage centres:** to take up on priority the provision of passenger amenities and beautification on stations at pilgrimage centres including Ajmer, Amritsar, Bihar Sharif, Chengannur, Dwarka, Gaya, Haridwar, Mathura, Nagapattinam, Nanded,
- Nasik, Pali, Parasnath, Puri, Tirupati, Vailankanni, Varanasi and Vasco; also intend to run Aastha circuit trains to connect important pilgrim centres.
- **Porters-** intend providing them with new uniforms and train them in soft skills, henceforth, to be called sahayak.
- **High Speed Rail:** passenger corridor from Ahmedabad to Mumbai being undertaken with the assistance of the Government of Japan. SPV for implementing high speed projects will be registered this month. Prime benefit would be providing IR with technology advancements and new manufacturing capability.

Entertainment: propose to invite FM Radio stations for providing train borne entertainment; extend 'Rail Bandhu' to all reserved classes of travelers and in all regional languages.

- **Passenger traffic** - Suburban traffic: in-principle approval for MUTP III received. Early award of tenders for elevated suburban corridors between Churchgate-Virar and between
- **CSTM-Panvel;** revive Ring Railway system in Delhi; launching a new investment framework for developing suburban systems in partnership with State Governments, development in Ahmedabad, Bangaluru, Hyderabad Chennai and Thiruvananthapuram on the anvil. Winning back the lost modal share
- **Expanding the freight basket of IR -** to start time-tabled freight container, parcel and special commodity trains on a pilot basis, container sector would be opened to all traffic barring coal, specified mineral ores and part-loads during the non-peak season. All existing terminals/sheds would be granted access to container traffic, where considered feasible.
- **Rationalising the tariff structure** – undertake review of tariff policy to evolve a competitive rate structure vis a vis other modes, permit multi-point loading/unloading and apply differentiated tariffs to increase utilization of alternate routes, explore possibility of signing long term tariff contracts with our key freight customers using pre-determined price escalation principles.
- **Building terminal capacity** - proposed to develop Rail side logistics parks and warehousing in PPP mode, 10 goods sheds will be developed by TRANSLOC, the Transport Logistics Company of India, in 2016-17. To soon inaugurate India's first rail auto hub in Chennai. Encourage development of cold storage facilities on vacant land near freight terminals. Local farmers and fisherman would be given preferential usage of the facility. A policy in this regard would be issued in the next 3 months.
- **Nurturing customers** - will appoint Key Customer Managers to liaison with our major
- **freight stakeholders;** each Zonal Railway will develop customer commitment charter indicating service level commitments of IR, will explore the feasibility of opening up leasing of general purpose wagons.

The New Indian Express

Budget Exposes Gandhis, Irrelevance of the Left

OPINION | BALBIR PUNJ

The author is a Rajya Sabha member and political commentator. Email: punjbalbir@gmail.com

Year after year, it is fun for journalists covering budget presentation in Parliament to watch the see-saw of the Sensex as the harassed Finance Minister reads out the financial horoscope of the nation that he has prepared with so meticulous a care. There are at first shouts as the horoscope is unrolled and then the sighs. It could be the reverse also, the sighs first and the hurrahs later. What finally counts is the reaction after the whole picture gets clear.

Last Monday, we saw a lot of the early downtrend in the Sensex and then up and then down and then up again. But comparing what used to happen on Day 2 by which everyone has had time to listen and analyse the full budget speech, most commentators have found that this time, the stock market index rose by 777 points and was, as described by most newspaper reports, "the single day gain for the index in terms of points since 18 May 2009". It was also the "highest in percentage terms since 20 September 2013."

Such rise, as the market cheers the current Finance Minister Mr Arun Jaitley, must be seen in the backdrop of what the depressing climate was for the stocks worldwide in the last several years with economies almost everywhere in downward spin. Worst, in the case of Japan where they were even considering printing the currency and dropping it from the sky to revive demand and the economy or in Europe where GDP of the Eurozone nations was creeping but refusing to climb or in the US where a two-point rise would mean opening the cork of the Champaign bottle.

With a 7 to 7.5 per cent GDP forecast in Mr Jaitley's third and crucially placed budget, every Indian could proudly claim that our country today has the highest growth rate in the world. Also in the context of worldwide stagnation and recent dramatic developments, with China acting as the proverbial beast in the china shop with its devaluation of its currency that brought forth a storm in the financial markets, India's rupee rose closing on Tuesday at 67.87 per dollar. The analysts earlier were bracing up for a fall to ₹70 a dollar! Cheers again.

Such backslap for the Finance Minister from the financial circles though welcome, is hardly the stuff he should be looking for in our country where still 50 per cent of the workforce, that is some 600 million, has to labour on the farms to make both ends meet. Two successive years of drought have depressed agriculture and agri-GDP growth is nowhere around the four per cent needed merely for sustenance. With even farm product exports that once reached the 40 billion dollar line per year now falling in response to worldwide stagnation, the farming community has been pushed into distress with some even driven to suicide.

Three cheers for Mr Jaitley and his colleagues in the NDA Government for responding boldly to the grim scenario in the farm sector. Only a self-confident and visionary Government would have declared in Parliament on Monday that in five years, the budget would double the income of the Indian farmer. Remember agricultural sector of the economy was growing at a miserable 1.2 per cent in the context of two successive droughts. No frank analysis of the farm sector would be relevant without looking at the past 60 years when the then ruling Congress kept the rural population tied to farming as the only readily available occupation for the 70 per cent of the country's population. The bulk of the villages were without electricity and therefore, without small and medium industries dotting the countryside. When the Congress talks of its so called pro-poor policies, it should also accept responsibility for the permanent agrarian depressed state.

> The high farmer suicide rates in Cong-ruled states tell their own story of how the poor were largely kept pinned down to their tiny piece of land that is too uneconomic to support any livelihood

The high farmer suicide rates in many parts of Congress-ruled states tell their own story of how the poor were largely kept pinned down to their tiny piece of land that is too uneconomic to support any livelihood by agriculture. The irrigation perspective spelt out in the NDA budget should be read in the context of how water was yet another area of scandal along with other scams in telecom spectrum, coal mine allocation, the Commonwealth Games spending etc during the Congress-led regime. During the Congress rule in Maharashtra, irrigation had been a long-term get rich quick means for its leaders along with their partners in the game, the NCP's sugar plus irrigation bosses. Most of the irrigation projects especially in Vidarbha area have seen works in progress for as long as 35 years. The game changer now is going to be the NDA government's determined move to revive and fast-track 23 of the 89 stalled irrigation projects in one year and the promise of adding eight million hectares in four years.

This programme has been described as "remarkable" especially in the same Vidarbha, the cotton belt of India, where the two partners in power, the Congress and the NCP made irrigation a convoluted means of personal enrichment and power grabbing during their time in government.Apart from farm sector, the other area of focus in the budget is the mid-rank entrepreneurs like the SMEs and the start-ups. The offer that the Government will pay the EPF contribution of the employers for three years and the institutional arrangement for start-ups to stand on their feet and fight the battle for new profitable ideas comes against the backdrop of changing economics in the global scene of stress at big corporation level that has seen stressed loans and banks caught in the burden of NPAs. A new India is emerging, an India of young men and women who can turn ideas into enterprises and enterprises into ideal employers forcing the Marxist class conflict ideologues to revise their understanding of history. What the BJP economic policy, so impressively explained in the first few paras of Mr Jaitley's speech, does is to connect the farming sector and the enterprising sector of people into a synthesis that stands to transform India.

The doubling of farmers' income will generate the necessary demand push for enterprises to rush for responding by creating or expanding market leaders at every level and the big spending on infrastructure will draw out labour from the farms to construction sites. This should prove the burial ground for the 19th century ideas of class conflict of the Left and the caste conflict platform of the Indian socialists. Equally, it challenges the Rahul Gandhi-led poor feeding, by promoting the poor and the unskilled to learn and earn in the place of waiting for hand outs from the Congress' scandal-ridden table.

The 2016-17 Budget : A Positive step in India's Transformation Process

• **Mukul Asher**

Abstract: This paper analyses Union Government of India's 2016-17 Budget, comprising the Railway Budget as well as the main Budget components. It is argued that this Budget should be viewed as a part of the process of transforming India towards meeting challenges of growth and competitiveness in a manner which eases the ordinary life of the citizens, and which encourages aspirations for a better quality of life. The paper discusses several seemingly small initiatives with disproportionately positive impact on outcomes, an important feature of competence in governance. The assessment criteria for transforming India include consistency with growth diagnostics, fairness, and preparing the country to rapidly progress towards an upper -middle -income category of nations. It provides examples of how in some cases, better efficiency in resource use and improved fairness can be achieved simultaneously. The paper concludes, that, on balance, India's 2016-17 Budget does improve India's public financial management, and advance the process of transforming India in the right direction.

India's Railways and Union Government Budgets (hence forth the Budget) for 2016-17 should be assessed as part of a continuing process of transforming India rather than as a stand-alone event (albeit the most important event of the year).

Any budget is constrained by past policies and developments, and it will have impacts which transcend the fiscal year. Broader domestic and global developments, and perceptions and expectations of the stakeholders are also relevant in formulating a Budget.

The current external environment of subdued global growth and global trade, low or negative nominal interest rates, and a pervasive sense of fragility globally are factors which formed a part of the broader context in which the 2016-17 Budget was formulated. The domestic economic

environment has also been challenging shaped by two continuous years of drought and a reduction in the resources available to the Central government in line with the recommendations of the 14th Finance Commission.

Given the above, the trade-offs are among different objectives (such as fiscal consolidation, sectoral priorities, giving impetus to "animal spirits", and assigning proper roles to the state-market and public-private-social enterprise sectors complementarities, were exceptionally difficult to manage in this Budget.

The Budget projects nominal GDP growth of 11 percent in 2016-17.Assessing the Budget including the implicit or explicit trade-offs, therefore requires nuanced judgments and understanding of how and over what period the government measures may translate into desired outcomes. The judgments of policymakers about political feasibility and readiness of the stakeholders to accept proposed initiatives are also relevant in the budget assessment.

As the Prime Minister Narendra Modi led government's overall aim is to Transform India, the extent to which the 2016-17 Budget constitutes a positive step in transforming India is arguably a sound basis for its assessment.

There are three aspects of the Transforming India aim which are relevant for assessing the 2016-17 Budgets.

First, does the budget meet growth diagnostics tests which are relevant for the Indian context?

Second, does the budget improve fairness by delivering public services and amenities to help improve quality of living (facilitating day to day activities through easier and wider accessibility and affordability), and quality of life (taking steps to address aspirations of the people for better quality of life)?

Third, does the Budget help prepare India's economy, polity, and society for progression from the lower-middle-income to upper-middle-income category of nation?

When assessed on the above three aspects, the Budget, on balance,

does indeed advance the Transforming India objective and facilitates India's progress towards moving up the income category as explained below. The Budget therefore deserves to be welcomed by all stakeholders who desire India to emerge as an important power globally.

Growth Diagnostics Tests

The analogy here is with medicine where few vital signs are examined to assess health. In growth diagnostics, these signs are fiscal consolidation as an important element of fiscal and macroeconomic sustainability, investments, both direct, and those that crowd-in private and other investments as a result of public investments; use of knowledge, including when it is embodies in technology; encouraging formation of human skills and generation of livelihoods; and progressing towards cooperative federalism.

In all these aspects, it is essential that large imbalances between demand side and supply side forces should not be permitted to arise, but if they do, then they are effectively addressed. In India, too often the demand-side forces have been increased significantly (in some cases through giving statutory power to certain rights), but supply side elements, whether in health, education, power, transport, and other areas have lagged considerably. This has led to significant distortions not just in economy, but also in society, which the current government has been attempting to address. The fiscal consolidation and perceived fiscal prudence are especially important in the current global environment.

The budget meets this objective fairly well. This is indicated by the reduction in fiscal deficit (3.5 percent as compared to 3.9 percent of GDP in 2015-16), revenue deficit (2-3 percent as compared to 2-5 percent), and total outstanding liabilities (47.1 percent as compared to 47.6 percent, and projected to decline to 44.4 percent in 2018-19).

These are to be achieved with projected constant tax revenue to GDP ratio of 10.8 percent; (with welcome provisions to reduce compliance costs and burden imposed on the rest of the economy in generating the revenue) and reasonable assumptions of 11 percent growth in nominal GDP (real plus inflation) for 2016-17; 12 percent in 2017-18, and 13 percent in 2018-19.The total government expenditure in 2016-17 is projected to

be INR 19.8 trillion.

The budget continues to focus on obtaining fiscal revenue from not just the current year's income, consumption, and production flows, but also from using state assets more productively.

This is indicated by the plan to generate INR one Lakh crore from spectrum sales. The change in the name of Department of Disinvestment to Investment and Public Asset Management also reflects the new mind-set in generating revenue and improving the accountability of state assets. The Union government is among the largest owner of assets, including land. They also can create property rights (such as spectrum, air-space rights, airline landing allocation rights etc.) to generate revenue. But this requires a good asset registry, and reforms in accounting, budget management system, competency in auctioning in the transparent and accountable manner, and re-skilling of relevant staff. Initiatives by the government to track and reward performance of the officials and of office holders should therefore be welcomed.

The Budget has taken a welcome step to discontinue the practice of classifying expenditure into Plan and Non-Plan expenditure from 2017-18. The States should be encouraged to follow this practice as well.

The Budget, particularly the Railway Component, has focused on obtaining better outcomes from budgetary outlays, widening the sources of revenue; including using assets of the railways more productively (a neglected area so far); and more competent use of the Public-Private-Partnerships (PPPs), including Indian Railways partnering with the State governments to make railway assets more productive, and thereby crowd-in additional investments by other parties.

The Budget's investment proposals are designed to improve productivity in the use of capital, and to crowd-in private investments from both domestic and global investors.

This suggests that merely focusing on the level of budgetary capital expenditure and increase (INR 2.18 trillion, growth of 4 percent), as some analyst have done, misses the main thrust of the Budget concerning investments.

Plan to award 10,000 km of highway contracts in 2016-17; higher tripling of allocation to INR 270 billion, for Gram Sadak Yojna with potential for large multiplier effects; connectivity with the northeast, and investment in urban transport systems, with long-neglected in Mumbai receiving priority in capital expenditure of the Railways; and investments in coastal shipping, with huge savings in logistics and transport time and costs; investment in Digital Depository of academic transcripts; investments to provide urban-type facilities in rural areas under the Rurban clusters, are only some of the examples of the growth diagnostics consistent design of investment proposals in the 2016-17 Budget.

The importance of other growth diagnostics signs is also evident from the Budget. Thus, Start-up India, Mudra (Micro Units Development and Refinance Agency) Bank, Digital India, and combination of Aadhar -Jan Dhan Yojna (involving opening of bank accounts, overdraft, and accident insurance coverage, under which 212.2 million accounts and INR 342 billion have been deposited by members); and use of mobile payment and other technology to directly transfer amount to the bank accounts of the beneficiaries; near tripling of issuing of E-tourist visas on arrival about 120,000 per month, all require significant and skill-mix process improvements, as well as the use of technology.

The cooperative Federalism initiatives of the Budget are exemplified by meeting the commitment to increase devolution to stakes by 55 percent as recommended by the 14th Finance Commission; involving States in recognizing centrally sponsored schemes; and the UDAY (Ujjwal Discom Assurance Yojna) scheme to revive power distribution companies in the States. The Real Estate (Regulation and Development) Bill passed on March 10, 2016 will also positively impact States.

The above brief overview of the Budget concerning growth diagnostics strongly suggests the following.

First the Budget incorporates insights from modern growth theory and experiences by aiming to generate many growth nodes for the country, to help diversify the economy, and increase its resilience.

Second, the proposals recognize that a combination of use of ideas and knowledge, process improvements, and reconfiguration of skill-mix

(but with requisite certification for signaling) is essential for good quality broad-based growth.

Third, it is encouraging India's entrepreneurship and business instincts, facilitating it by better accessibility, affordability, and reliability of basic public amenities, particularly physical and digital connectivity.

Improving Fairness

It is widely acknowledged that corruption at the higher levels of the Union Government that was previously ubiquitous with the Congress-led government's tenure has been nearly eliminated, if not completely. As with inflation, corruption hurts the bottom-half of the population particularly hard. This factor has improved the fairness of fiscal operations and enhanced stock of social capital or trust significantly. This aspect has not been sufficiently acknowledged by the commentators.

The 2016-17 Budget also continues the focus of the current government to improve fairness by making basic public amenities more accessible, affordable, while improving their reliability. These in turn will positively impact on the quality of living of India's households, facilitating their daily lives.

Illustrative examples from the Railway component of the budget include:

A Centrally managed "Railway Display Network" to provide information

Addition to seats in general class on busy travel nodes Measures to improve cleanliness and hygiene facilities on stations and in trains Railways Research centers to continue to improve services.

An example from the Power sector includes the Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna (DDUGJY) under which 35 percent of 18, 452 currently un-electrified Villages have already been electrified. This in turn will not only improve quality of living, but also widen livelihood opportunities for the villagers, facilitating inclusive broader-based growth.

The transparent nature of this power initiative is exemplified by the continuous updating of the progress in electrification of villages by visiting http://garv.gov.in/dashboard . The use of dashboard as a technique,

usually used by effective managers, reflects focus in outcomes of policy initiatives, rather than on government expenditure, which constitute only financial (not even physical) inputs.

The Pratyaksh Hanstantrit Labh (PAHAL) scheme under which subsidies for cooking gas are transferred directly to the beneficiaries, and the accompanying for citizens to voluntarily not avail of the subsidy (6.5 million citizens have already voluntarily given up the subsidy), whose savings are channeled to giving new gas connections for low income families, improves both fairness and growth prospects while reducing leakages, thus improving expenditure management. The use of cleaner energy sources would also potentially improve maternal and child health.

The focus on outcomes enhances the fairness of the initiatives, a point missed by many analysts who only compare financial inputs, without understanding the processes by which such inputs are to be turned into outputs and then into outcomes focusing on improving household welfare.

The Budget also provides for meeting the pension benefits, including arrears, to the military personnel who, for the first time, were promised "One-Rank-One-Pension" by the current government. This is an issue of fairness as the earlier governments implemented such arrangements only for the civilian, but not for the military personnel.

The Budget and related measures also contain initiatives to address natural and other risks faced by households by specific risk-mitigation and management Programs. These include, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY) to provide insurance cover and stabilize farm incomes in the event of natural calamities, pests, and diseases (http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=134432 , a dedicated long term irrigation fund, program to make ground-water resources more sustainable; reconfiguring MGNREGA (Mahatma Gandhi National rural employment guarantee act) scheme to help generate such productive assets as ponds, wells, and compost pits to reduce farm risks and new health insurance scheme.

There are also initiatives to improve quality of life by meeting aspirations of the citizens to significantly improve their economic prospects

and social position. Some of the initiatives such as Start-Up India, Mudra Bank have been mentioned.

Proposal to double farm incomes by 2022, an achievable goal, would potentially improve quality of living and of life. Empowering powers through greater economic freedom and access to technology will assist in this goal.

Perhaps bolder measures to reform education and research institutions, with much more accountability for outcomes, could have served this objective to even greater extent.

Preparing India to Progress towards Upper-Middle-Income Category

The analysis under growth diagnostics and fairness above, attempting to channel energies of the stakeholders into nation building, and efforts being made to shift political accountability based on improving citizen's quality of living and of life suggest that the Government is preparing the country towards challenges of moving up the income category. This is however rarely a linear process. The Budget however does lay solid groundwork for managing India's future.

Some Measures Needed Greater Preparation

There are some proposals in the budget for which better background work were needed. An example includes the method (but not the intent) of encouraging widening access to retirement income security by levying tax on EPF (Employee's Provident Fund) accumulations.

Pension economics is subtle, has tyranny of small numbers where seemingly small changes can have disproportionate impact; and requires long-term policy stability and credibility. A systematic rather than a scheme-based ad-hoc approach to achieve the Budget's intent is needed.

There is an urgency to develop international financial services in India. To achieve this, greater clarity on their tax and other regulatory aspects, and for such products as "Masala Bonds", INR denominated bonds listed abroad, in which exchange rate risk is borne by the lender not the Indian borrower, could have been forthcoming in the budget. Perhaps as with banking sector reforms, and bankruptcy law reform, these will be undertaken outside the Budget.

There is a need for greater urgency in passing the Constitutional Amendment Bill for GST (Goods and Services Tax). Insistence by the opposition Congress party that the rate of GST be made as part of the Bill should be rejected outright as inimical to the spirit of any tax Bill. The so-called "origin" states must be persuaded to drop their insistence on levying 1 percent additional GST rate on inter-state sales. Such sales should not attract any tax to realize full benefits from GST. States will not lose revenue as the Union government has agreed to reimburse to the States any shortfall in sales tax revenue for five years.

Concluding Remarks

The 2016-17 Budget must be viewed as a part of the process of transforming India towards meeting challenges of growth and competitiveness in a manner which eases the ordinary life of the citizens, and which encouraging aspirations and hope for better quality of life. As argued above, the 2016-17 Budget does advance the process of transforming India in the right direction.

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

https://web.facebook.com/spmrfoundation

https://twitter.com/spmrfoundation